

शहर	अधिकतम	न्यूनतम
धनबाद	33.1	27.5
जमशेदपुर	33.5	26.0
डाल्टनगंज	32.8	26.3

तापमान डिग्री सेल्सियस में.

\* \*

रांची, धनबाद एवं पटना से प्रकाशित

# शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार



www.lagatar.in

रांची, शुक्रवार 26 जुलाई 2024 • श्रावण कृष्ण पक्ष 05 संवत् 2081 • पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹ 10 • वर्ष : 2, अंक : 108

आमंत्रण मूल्य : ₹ 3 मात्र



वादा से ज्यादा  
आपके लिए करेंगे,  
125 नहीं अब

**200**  
यूनिट बिजली मुफ्त देंगे

जे.बी.वी.एन.एल से  
व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ें  
9431135503

**बिजली की बचत करें,  
झारखण्ड को उन्नत करें**

## मुख्य बिन्दु

- ⚡ आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- ⚡ यह योजना जुलाई 2024 के बिलिंग माह से लागू किया जाएगा।
- ⚡ इस योजना के तहत कुल 45.77 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 41.44 लाख घरेलू उपभोक्ता आच्छादित होंगे।
- ⚡ 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी तरह के शुल्क यथा Energy Charge, Fixed Charge, Electric Duty, FPPPA Charge आदि की छूट 200 यूनिट तक मासिक स्वपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
- ⚡ 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना हेतु झारखण्ड सरकार प्रतिमाह लगभग ₹350 करोड़ सब्सिडी के रूप में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायेगी।



**हेमन्त सोरेन**  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार



# बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत पर साधा निशाना, कहा - गलतफहमी पालकर आखिर कितने दिन आखें बंद रखेंगे उटिए, जागिए महाराज, देखिए आपके पीछे कोई नहीं बचा है...

प्रमुख संवाददाता। रांची

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से तार्किक अंदाज में सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। कहा है कि गलतफहमी पालकर कितने दिन आखें बंद रखेंगे। उटिए, जागिए महाराज, देखिए आपके पीछे अब कोई नहीं बचा है। और हां, थोड़ी सी भी मर्यादा और इंसानियत बची हो तो नामजद सहायक पुलिसकर्मियों का नाम एफआईआर से वापस लें। चाहे आप अपनी हड्डियों का बचा पूरा दम भी क्यों न लगा लें... अधिकारों के मिलने तक, मांगों के पूरा होने तक यह संघर्ष अनवरत चलता रहेगा, यह बिगुल हरदम बजता रहेगा।

## दनादन परीक्षाएं की जा रही हैं स्थगित

बाबूलाल ने टवीट में आगे लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, आपने तो जमानत पर जेल से छूटने के बाद चंपाई सोरेन जी द्वारा घोषित 40,000 नौकरियों में 25% कटौती कर के 30,000 नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन अब तो प्रतिदिन दनादन युवाओं को नौकरी देने की नीयत नहीं

परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। इस आघापी की वजह क्या है? क्या आयोग ने सरकार के दबाव में अघुरी तैयारी के साथ परीक्षा की तिथि घोषित कर दी थी? क्या आपको नौकरी बेचने का मनचाहा 'रेट' नहीं मिल रहा?

## ये कैसी सरकार है....

जहां पहले अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, फिर लाठी खानी पड़ती है और अंत में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर झूटी एफआईआर भी लिखी जाती है। जब बात खुद सत्ता में बैठकर आदेश देने की आती है, लोगों पर एफआईआर कराने की आती है तो महोदयों को आदिवासी समाज नहीं दिखाते हैं। नामित नामों को देखें तो 18 में से लगभग 11 से 12 नाम आदिवासी भाई - बहनों के हैं, और अभी 1500 अज्ञात लोगों में से न जाने और कितने आदिवासी होंगे।

## 'बच्चों को घटिया खाना खिला रही हेमंत सरकार'

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने टवीट कर कहा है कि हेमंत सरकार झारखंड के आदिवासी बच्चों को घटिया खाना खिला रही है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन बेहद जरूरी होता है, लेकिन झारखंड के अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में आदिवासी बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता बेहद घटिया है। हेमंत सोरेन से कहा कि कुछ तो लाज-शर्म रखिए और शिक्षा के मंदिर को अपने भ्रष्टाचार का केंद्र मत बनाइयें। डीसी रांची को कहा कि

यथाशीघ्र संबंधित विद्यालय में पौष्टिक भोजन और पढ़न-पाठन की सुचारु व्यवस्था का प्रबंध करें। झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार : बाबूलाल ने दूसरे टवीट में कहा कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड राज्य के लिए 7302 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009-14 के औसत बजट 457 करोड़ से अधिक है। हेमंत सोरेन से कहा कि कुछ तो लाज-शर्म रखिए और शिक्षा के मंदिर को अपने भ्रष्टाचार का केंद्र मत बनाइयें। डीसी रांची को कहा कि

# रांची, धनबाद व जमशेदपुर में एयर व्वालिटी के लिए मिले 150 करोड़

■ धनबाद और जमशेदपुर को 100 में 100 और रांची को मिले 75 अंक

## प्रमुख संवाददाता। रांची

झारखंड के शहरी विकास और आवास सचिव अरवा राजकमल ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की 7वीं संचालन समिति की बैठक में भाग लिया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए चयनित शहरों में झारखंड के तीन शहरों में रांची, धनबाद और जमशेदपुर शामिल हैं। सचिव ने बैठक में इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया है और 2024-25 में फंड के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

# कोर्ट की खबरें : हाईकोर्ट के नए भवन में जलजमाव पर जनहित याचिका की हुई सुनवाई पार्किंग में जलजमाव, कोर्ट नाराज

संवाददाता। रांची

झारखंड हाईकोर्ट ने पार्किंग एवं अन्य जगहों पर जलजमाव पर नाराजगी जतायी है। नयी हाईकोर्ट बिल्डिंग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि झारखंड हाईकोर्ट परिसर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाये। इसको लेकर अदालत ने राज्य सरकार को भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे अरसे से झारखंड हाईकोर्ट के नये परिसर के निर्माण की मांग हो रही थी। इतनी बड़ी रकम से बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पूरे होने के बावजूद अगर इस तरह जलजमाव का सामना करना पड़ रहा है तो यह निराशा जनक है। मामले को अगली सुनवाई अगस्त माह में होगी। बता दें कि बारिश से हमेशा हाईकोर्ट की पार्किंग में जल जमाव हो जाता है।

## प्रेम प्रकाश की डिस्टार्ज पिटीशन पर बहस पूरी

रांची। चेसाय्यर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े लैड स्केम केस के आरोपी और पवार ब्रॉकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की डिस्टार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए (प्रोवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार को ईडी और प्रेम प्रकाश की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

## ऊर्जा सचिव को 31 अगस्त को उपस्थित होने का निर्देश

रांची। राजेश कुमार सिंह द्वारा विद्युत विभाग में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ऊर्जा सचिव को 31 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि 2003 में जब एक्ट आया तो 2024 तक इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। अदालत अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। राजेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत की जानी चाहिए, इस मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने पक्ष रखा। वहीं विद्युत नियामक आयोग की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा।

## आलमगीर-बीरेंद्र का केस एक साथ टैग, होगा चार्ज फ्रेम

रांची। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के निर्लिखित इंजीनियर इन चीफ बीरेंद्र राम से जुड़े टेंडर घोटाला के दो मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया है। रांची पीएमएलए (प्रोवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में गुरुवार को इस केस की आरोपी राजकुमारी देवी और बीरेंद्र राम के पिता गोंदा राम सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया। अब न्यायालय चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू करेगा। टेंडर घोटाला के जरिए मनी लॉन्डिंग की जांच कर रही ईडी : दरअसल झारखंड में टेंडर घोटाला के जरिए मनी लॉन्डिंग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस केस में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उसके ओएसडी संजिव लाल और जहांगीर आलम समेत ग्रामीण विकास विभाग के निर्लिखित इंजीनियर इन चीफ बीरेंद्र राम समेत कई लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है।

## राज्य सेवा के अफसरों का ताबड़तोड़ तबादला

# 61 बीडीओ का हुआ ट्रांसफर

प्रमुख संवाददाता। रांची। राज्य सेवा के अफसरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। 61 बीडीओ को इधर से उधर कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि वैसे प्रखंड जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहां अधिसूचित कार्यरत अंचल अधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी की शक्ति नियमित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदस्थान तक प्रदत्त की जाती है। जिन प्रखंडों में भी अधिकारी के पद रिक्त हैं, उनमें प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा अंचल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

जानें कौन-कहां गए					
चंद्र देव प्रसाद	बीडीओ	चंदबारा, कोडरमा	अजय कुमार वर्मा	बीडीओ	डुमरी, गिरिडीह
नूपुर कुमारी	बीडीओ	कटकमसांडी	पप्पू राजक	बीडीओ	हरदरांग
अमित कुमारी	बीडीओ	सदर गुमला	अमल जॉ	बीडीओ	पालोजरी,
कुन्दन भगत	बीडीओ	मोहनपुर	अमरेन डांग	बीडीओ	रंका, गढ़वा
रणजीत कुमार सिन्हा	बीडीओ	दुलमी	कीकू महतो	बीडीओ	कुंदा चतरा
कमलेश कुमार सिन्हा	बीडीओ	शिकारीपाड़ा	देवानन्द राम	बीडीओ	देवघर सदर
आशा साहू	बीडीओ	बरणपुर, रामगढ़	सुनील वर्मा	बीडीओ	चित्रपुर, रामगढ़
शक्ति कुंज	बीडीओ	रायडीह गुमला	मनोरेज कुमार	बीडीओ	पथलगाड़ा, चतरा
सत्यम कुमार	बीडीओ	विष्णुगढ़	मनोज कुमार तिवारी	बीडीओ	डडई, गढ़वा
दयानंद प्रसाद जायसवाल	बीडीओ	महुआटाइ	ललित प्रसाद सिंह	बीडीओ	झोंकपानी, प. सिंहभूम
मो. हारून रशीद	व्याख्याता	सई	संजय कुमार कोनगाडी	बीडीओ	पदमा हजारीबाग
संजय सांडिल्य	बीडीओ	बेर्मा	आकांक्षा कुमारी	बीडीओ	गोंडू सदर,
रितोक कुमार	बीडीओ	मांडू, रामगढ़	कनक	बीडीओ	बुड़ू रांची
बुरेण कुमार	बीडीओ	कुरुडंग	विवेक किशोर	बीडीओ	कुकुडू, सरायकेला
रेणु कुमारी	बीडीओ	मांडर	संतोष कुमार महतो	बीडीओ	गारू, लातेहार
संदीप कुमार	बीडीओ	मनिंका लातेहार	हरिशंकर बारिक	बीडीओ	विश्रामपुर, पलामू
सोमनाथ बर्जाई	बीडीओ	रातू रांची	अखिलेश कुमार	बीडीओ	मंडीआंव, गढ़वा
ज्ञानमणी एक्का	बीडीओ	केरसाई, सिमडेगा	संतोष कुमार चौधरी	बीडीओ	बारियातू, लातेहार
मो. अमीर हमजा	बीडीओ	जामा दुमका	अशोक कुमार चौपड़ा	बीडीओ	मनातू, पलामू
विजय प्रकाश मरांडी	बीडीओ	नाला, जामताड़ा	मनोज कुमार गुप्ता	बीडीओ	राहे, रांची
अनिल कुमार	बीडीओ	तिसरी गिरिडीह	विजय कुमार	बीडीओ	हरिहरगंज पलामू
प्रभाष चंद्र दास	बीडीओ	जलडेगा, सिमडेगा	संतोष कुमार	बीडीओ	नोडीहा बाजार, पलामू
विवेक कुमार	बीडीओ	ईचाक	चन्दन प्रसाद	बीडीओ	दारू, हजारीबाग
सुमित कुमार मिश्रा	बीडीओ	केरेडारी, हजारीबाग	ठाकुर गौरी शंकर शर्मा	बीडीओ	लोहरदागा सदर
अमित कुमार पासवान	बीडीओ	चंदवा	निखिल गौरव कमान कच्छप	बीडीओ	खुटपानी, प. सिंहभूम
प्रवीण कुमार	बीडीओ	रामगढ़, पलामू	विशाल कुमार पाण्डेय	बीडीओ	टुंडी, धनबाद
अभिषेक पाण्डेय	बीडीओ	प्रतापपुर चतरा	अन्वेधा ओना	बीडीओ	चांडील,
कामेश्वर बेदिया	बीडीओ	ओरमांडी	मनीष कुमार	बीडीओ	धुरकी, गढ़वा
तालेश्वर रविदास	बीडीओ	पतरातू रामगढ़	अजय कुमार दास	बीडीओ	चिनियां, गढ़वा
प्रदीप कुमार दास	बीडीओ	पाकरटाई, सिमडेगा	मनीष कुमार	बीडीओ	नामकुम, रांची
शैलेन्द्र कुमार चौरसिया	बीडीओ	बगोदर, गिरिडीह			

## ब्रीफ खबरें

### सुप्रिम कोर्ट ने झारखंड का हक लौटाया : ठाकुर

रांची। प्रदेश कांग्रेस ने रतनगर्भा झारखंड और अन्य राज्यों द्वारा खदान और खनिज संसाधनों पर कर लगाने के मामले में सुप्रिम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक करार देते हुए इसका स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा खनिज और खदानों पर राज्यों द्वारा कर लगाने के अधिकार के पक्ष में फैसला देना एक ऐतिहासिक निर्णय है, उन्होंने कहा कि 35 वर्षों पूर्व के फैसले को अमान्य करार देकर उच्चतम न्यायालय ने झारखंड को उसका हक वापस लौटा दिया।

### राजधानी में आज बनेगी मानव श्रृंखला

रांची। आदिवासी जमीन लूट और पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में आदिवासियों की मातृभाषा कुड़ुख, मुंडारी, खड़िया, संथाली, हो आदि के स्थान पर सादरी और नागपुरिया के शिक्षक नियुक्ति के विरोध में 26 जुलाई को एक दिवसीय मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन सुबह नौ बजे से हरमू बाईपास रोड में पुरानी रांची से लेकर बिरसा चौक तक किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष संगम उरांव ने दी है।

## आंदोलनकारियों को मिलेगा बकाया पेंशन

रांची। झारखंड अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को बकाया पेंशन का भुगतान किया जायेगा। यह बकाया पेंशन रांची, जामताड़ा, लातेहार, चतरा और गढ़वा जिले के आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को मिलेगा। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तीस लाख की राशि आवंटित की है। इसको लेकर गृह सचिव ने आदेश जारी

# सूबे के पांच जिलों के रहने वाले 15 नक्सलियों की तलाश में एनआईए

रांची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) रांची, धनबाद, लातेहार, लोहरदागा और चतरा जिले के रहने वाले 15 बड़े नक्सलियों की तलाश में है। इन नक्सलियों के सहयोगियों से एनआईए जानकारी जुटाने में लगी है। एजेंसी ने पिछले दिनों कुछ सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बता दें कि एनआईए झारखंड टेरर फोडिंग, माओवादी उग्रवाद और मानव तस्करी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रही है। इन सभी मामलों में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। साथ ही कई नक्सली, उग्रवादी और टेरर फोडिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

## इन 15 बड़े नक्सलियों की है तलाश

- गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला भाकपा माओवादी का नक्सली पतिराम मांडी को एनआईए कांड संख्या आरसी-11/2017 और आरसी -19/2018 और 25/2020 मामले में तलाश कर रही।
- धनबाद टुंडी का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली प्रयाग मांडी को एनआईए कांड संख्या आरसी-11/2017 में खोज रही।
- रांची बुंडू का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली गुरुवा मुंडा को एनआईए कांड संख्या आरसी-11/2017 में तलाश कर रही।
- भाकपा माओवादी नक्सली छोटू खेरवार को एनआईए कांड संख्या आरसी 14/2017 और आरसी 01/2018 और 25/2020 में तलाश कर रही है।
- चतरा लावालौंग का रहने वाला टीपीसी उग्रवादी बुजेश गंडू को एनआईए कांड संख्या आरसी 06/2018, आरसी 22/2018 और आरसी 23/2018 में ढूंढ रही।
- चतरा जिले के लावालौंग का रहने वाला आक्रमण गंडू को एनआईए कांड संख्या आरसी 06/2018, आरसी 22/2018 और आरसी 23/2018 में तलाश कर रही।
- गिरिडीह जिले के मधुवन का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली रामदयाल महतो को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/2018 मामले में खोज रही।
- गिरिडीह जिले के पीरटांड का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली अजय महतो को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/ 2018 में तलाश कर रही है।
- गिरिडीह डुमरी का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली चंचल को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/2018 में ढूंढ रही।
- गिरिडीह जिले के अकबोकाटांड का रहने वाला भाकपा माओवादी नक्सली शनीचर हेबरम को एनआईए कांड संख्या आरसी 19/2018 में तलाश कर रही है।
- लातेहार का रहने वाला रवींद्र गंडू को एनआईए कांड संख्या 25/2020 में तलाश कर रही है। इसके अलावा इस मामले में एनआईए मृत्युंजय भुंड्या, नागेंद्र यादव, कुंदन खेरवार, अनिल तुरी की भी तलाश कर रही है।

**वलासिफाइड**

Free DEMO 2days

# DANCE CLASSES

DIPLOMA OF COMPLETION

6207234659 | 9334621159

www.asma.org

Regd. No. 2026/RAN/4761/BKA/378

# TULSI PUBLIC SCHOOL

A Unit of Public Charitable Trust "LOKCHETNA"

## CLASS

Nursery to V  
CBSE PATTERN

ADMISSIONS OPEN

CREATE THE BEST FUTURE YOUR CHILD

VII - Boladib, Talai Nagar, Post - Boladib, West Singhbhum, Thata- Tokla, Block Chakradharpur, Jharkhand - 831102, Mob. - 9603711115

BAHARAGORA, NEAR - R.V.I.School

# OXYRIVER Aqua

With Minerals

Swapan Kumar Paul Mob. : 70918 66623

PLEASE SEND YOUR RESUME FOR AN INDUSTRIAL AUTOMATION ORGANISATION, MOSTLY ENGAGED WITH PRESTIGIOUS PROJECTS IN

# TATA STEEL, UCIL, ISRO, BARC ETC

1. **MARKETING MANAGER** : SALARY 2.4 LAKHS PA, ITI, DEE, BEE FOR JAMSHEDPUR, SALES PLC SCADA HMI KNOWLEDGE, experience 5 years

2. **OFFICE ASSISTANT** : SALARY 2.4 LAKHS PA, Graduate with 5 Years Work Experience Computer Proficient, Knowledge About Tender and TATA STEEL PROCUREMENT

MAIL CV : pradep\_wk@yahoo.com

**Anne Children Clinic**

The Complete Shishu Care

Sr. Consultant

# Dr. Aman Urwar Aaash

M.B.B.S, D.C.H., P.G.P.N. CHILDREN HOSPITAL (A Unit of ANHRC)

Child & Newborn Specialist

**फाहिमा अकादमी एप्लीकेटेड स्कूल**

नीचोएरईय नैट्सकी हजारीबाग

**फैसिलिटी**

खैल खेलकौ, गैलरी, योग, गैमिफिक, स्कूल बरौ कीरिबोडि, एम्प्लॉय वलादेज निवेदक

# मोहम्मद अली

स्कूल हायवेस्ट

घात : कल्लू चौक नियट पेट्रोल पंप हजारीबाग

22 वर्ष से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन

## 14th JPSC PT & Mains

Foundation Batch in our Hazaribag Branch

Office Class (Hazaribag Branch)  
Under Guidance of Pawan Jha Mentor : Mr. Harsh Wadhwa (Administrator, Jhumsitilaya Municipal Council)

Fee PT- Rs. 1000/-  
Mains - Rs. 21000/-  
Time : 8 am

Mob : 9608711477 www.vijaystudycircle.com

Head Office : Shanti Bhawan, Albert Ekka Chowk, Ranchi  
Branch Office : Bhowani Plaza, S.P. Rana Enclave 1st Floor, West of Banshi Lal Chowk Malviya Marg, Hazaribag-825301

## जेडी स्कूल बड़कागांव रोड हजारीबाग

योग शिक्षक... आधुनिक सुविधा ...

बेहतरीन शिक्षा की गारंटी....

निवेदक

# विनोद भगत

संपर्क करें 9835755523

**GYAN JYOTI COLLEGE OF PHARMACY, PARAMEDICAL & NURSING**

NEAR PWD Chowk, Hazaribag, Jharkhand, India

9431505777, 7870145555, 8789274448

**Paramedical**

- B.Sc BMLT
- DMLT
- OF Assistant
- X-Ray Technician
- Dresser

**PHARMACY**

- DIPLOMA IN PHARMACY
- B.Pharm
- M.Pharm
- D.Pharm

**NURSING**

- ANIM
- B.Sc. Nursing
- M.Sc. Nursing
- PGDIPLOMA IN NURSING



# शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार



www.lagatar.in

रांची, शुक्रवार 26 जुलाई 2024 • श्रावण कृष्ण पक्ष 05 संवत् 2081 • पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹ 10 • वर्ष : 2, अंक : 108

आमंत्रण मूल्य : ₹ 3 मात्र

## झारखंड के हक में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, केंद्र को झटका खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार

लगातार न्यूज नेटवर्क

सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि खान-खनिज की माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है, वह टैक्स नहीं है। माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है या नहीं है, इसे लेकर करीब 25 सालों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि झारखंड में कोयला, आयरन ओर (लौह अयस्क), तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, मैंगनीज समेत कई तरह के खनिज हैं। सरकार को सिर्फ रॉयल्टी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार अपने स्तर से खनिजों की माइनिंग पर टैक्स लगा पाएगी। इससे राज्य सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। इसे विंडबना ही कहा जाएगा कि झारखंड के पास खनिजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी केंद्र नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों को फायदा होगा। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के पास निकालने वाले खनिजों पर कर लगाने की सीमाएं, प्रतिबंध और यहां तक कि रोक लगाने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत राज्यों के पास खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। शीर्ष अदालत की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी केंद्र नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों को फायदा होगा। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के पास निकालने वाले खनिजों पर कर लगाने की सीमाएं, प्रतिबंध और यहां तक कि रोक लगाने की शक्ति है।

1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया

### 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को गलत ठहराया

- 9 जजों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से कहा-रॉयल्टी टैक्स नहीं है
- कहा- एमएमआरडीए एक्ट राज्यों के अधिकार सीमित नहीं करता

#### न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ला फैसले से असहमत

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ला ने कहा कि राज्यों के पास खनिजों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस और नागरत्ला के अलावा पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति शिबिरी, अमर ए.एस. ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति आंग्रेस्टीन जॉर्ज मसीह हैं।



#### 31 जुलाई को पीठ सुनाएगी अपना फैसला

पीठ ने इस विवादस्पद मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कर है, क्या केवल केंद्र को ही ऐसा कर लेने का अधिकार है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लेने का अधिकार है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ ने केंद्र और राज्यों से इस पहलू पर लिखित दलीलें दखिल करने को कहा और कहा कि वह 31 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला करेगी। अगर यह फैसला पूर्वव्यापी लागू होता है, तो राज्यों को भारी कर बकाया देना पड़ सकता है। राज्य चाहते हैं कि यह फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू हो, जबकि केंद्र इसे भविष्य के लिए लागू करना चाहती है।

#### कोर्ट ने क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मिनरल्स वाली जमीन पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। इससे ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान को बड़ा फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, रॉयल्टी खनिज पर देय है, रॉयल्टी खनिज में निकाले गए मिनरल्स की मात्रा के आधार पर तय की जाती है। रॉयल्टी की बाध्यता पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले के बीच अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करती है। इसके लिए जो भी पैमेंट होती है, वह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि विशेष उपयोग शुल्क के लिए होता है। ऐसे में सरकार को अनुबंध के लिए किए गए भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता। मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है। रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है। हमारा मानना है कि इंडिया सोमेट्स के फैसले में रॉयल्टी को टैक्स बताना गलत है।

#### केंद्र की दलील- रॉयल्टी का अधिकार केंद्र के पास है

केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने तर्क दिया था- केंद्र के पास खनिज और खनिजों पर टैक्स लगाने की ज़्यादा शक्तियां हैं। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि खनिज और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम खनिजों पर टैक्स लगाने को राज्यों की विधायी शक्ति पर सीमा लगाती है और रॉयल्टी तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य सरकारों के द्वारा खनिज पर रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने का विरोध किया था। केंद्र ने अदालत से राज्यों द्वारा रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने की अनुमति ना देने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि खनिज समृद्ध राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स से महंगाई बढ़ेगी। खनिज क्षेत्र में एफडीआई में बाधा आएगी। भारतीय खनिज महंगा हो जाएगा। व्यापार घाटे में वृद्धि और राज्यों के बीच विषम आर्थिक विकास के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

क्या है रॉयल्टी : कर्पणियां खनिज की मात्रा के अनुपात में निकाले गए खनिज के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करती हैं। इस तरह के भुगतान को रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी की गणना निकाले गए या हाटए गए खनिजों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

#### किसका कितना बकाया (रुपये में)

राज्य	बकाया	राज्य	बकाया
ओडिशा	1798369.46 लाख	महाराष्ट्र	30453.66 लाख
छत्तीसगढ़	883872.12 लाख	गुजरात	25165.11 लाख
राजस्थान	367596.65 लाख	तेलंगाना	22473.79 लाख
झारखंड	279140.34 लाख	तमिलनाडु	17936.39 लाख
आंध्र प्रदेश	41402.136 लाख	गोवा	9755.24 लाख
कर्नाटक	254214 लाख	यूपी	2452.32 लाख

#### फैसला सही नहीं : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और पीठ के सात जजों के फैसले को पढ़ा, जिसमें कहा

गया कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। बहुमत के फैसले में कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1989 में सात जजों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया

वह फैसला सही नहीं है, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है।

शेष पेज 11 पर

## कारगिल विजय दिवस आज



भारत ने 26 जुलाई, 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल में विजय पताका फहराया था। इसके बाद से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है, जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी, साथ ही यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कारगिल दिवस के दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी व गैर-सरकारी शौकिक और अन्य संस्थानों में समारोह आयोजित किए जाते हैं।

#### ऑपरेशन विजय के नाम से भारत ने चलाया था अभियान

26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, 60 दिन तक कारगिल चला युद्ध-527 जवान हुए थे शहीद, करीब 1400 जवान घायल हुए

## जेपी पटेल व लोबिन की विधायकी गई, स्पीकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रमुख संवाददाता। रांची

विधानसभा सदस्य जेपी पटेल और लोबिन हेमंत की विधायकी चली गई। विधानसभा स्पीकर कोर्ट ने गुरुवार को इसका फैसला सुना दिया। पिछले दो दिनों से इस मामले की सुनवाई स्पीकर कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही दोनों से गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा गया था। दोनों की ओर से लिखित जवाब मिलने के चार घंटे बाद स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया। दोनों को दल-बदल मामले में दसवीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए दोषी माना गया। इन दोनों विधायकों की सदस्यता 26 जुलाई से रद्द मानी जाएगी।

पार्टी लाइन से बाहर जाकर लोबिन ने लड़ा था चुनाव : झामुमो विधायक लोबिन हेमंत ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित

#### दसवीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए दोनों को माना दोषी



26 जुलाई से मानी जाएगी दोनों की सदस्यता रद्द  
दोनों के लिखित जवाब देने के चार घंटे बाद स्पीकर ने सुनाया फैसला

#### कांग्रेस के टिकट पर जेपी पटेल ने लड़ा था चुनाव

वहीं, भाजपा विधायक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गये थे और हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दल-बदल की शिकायत की थी। सुनवाई के दौरान अमर बाउरी ने पूछा था कि विधायक केवल इतना बता दें कि वह कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे या नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल ने इस पर कहा था कि मुझे मंगलवार को ही याचिका की कॉपी मिली। इसलिए मुझे जवाब के लिए 90 दिनों का समय चाहिए। इस पर स्पीकर ने उन्हें गुरुवार को ही जवाब देने को कहा था।

करते हुए दल-बदल की शिकायत की थी। वहीं विधायक लोबिन हेमंत की ओर से कहा गया कि इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है। सदन में हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट किया था। इसका मतलब है कि वे झामुमो के ही विधायक हैं। वहीं झामुमो की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोबिन हेमंत ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा। ऐसे में उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए।

#### सर्कारा

सोना (बिक्री) 64,800  
चांदी (किलो) 87,000

#### ट्रीफ खबरें

#### महाराष्ट्र में बारिश का कहर, इलाके जलमग्न



पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच गुरुवार को को वर्षाजलित घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुणे समेत महाराष्ट्र के कई निचले इलाके जलमग्न हो गये हैं। मुंबई में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। गुजरात में भी बारिश का कहर जारी है। पेज 12 भी देखें

#### केजरीवाल के समर्थन में 30 को 'इंडिया' की रैली

नयी दिल्ली। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक रैली आयोजित करेगा, जिसमें तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

#### दरवार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदले गए

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरवार हॉल और अशोक हॉल के नाम गुरुवार को बदल कर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिए गए। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 'शहशाह' का कॉन्सेप्ट है।

## लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उठाया सवाल, की मांग, मचा हंगामा संथाल के 10% आदिवासी कहां गुम हो गए?

एजेंसी। नयी दिल्ली

गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने शुरुआत संविधान खतर में है से की ओर कहा कि हम यहां दलितों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं। कहीं किसी की सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। सांसद ने कहा, जिस संथाल परगना से आता हूं, वहां जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आदिवासी आबादी 36% थी। आज आदिवासियों की आबादी 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए?

123% की दर से बढ़ी मुस्लिम आबादी : सांसद ने कहा कि जिन की जो अध्यक्ष हैं, उनके पति मुसलमान हैं। हमारे यहां जो आदिवासी मुखिया हैं जो आदिवासी के नाम पर हैं और उनके



पति मुस्लिम हैं। प्रत्येक चुनाव में 15 से 17% आबादी बढ़ती है, हमारे यहां 123%। दुबे ने कहा कि जिस लोकसभा से चुन कर आया, उसकी एक विस सीट मधुपुर में 267 व्यूथों पर मुस्लिमों की आबादी 117% बढ़ गई है। झारखंड में 25 एसी विस सीटें हैं जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये बड़ी चिंता

#### झारखंड की 25 विस सीटों पर बढ़े 110% मुस्लिम, गांव के गांव हो गए खाली

बांग्लादेशी कर रहे यहां की लड़कियों से शादी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वोटबैंक की पॉलिटिक्स करता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे यहां जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घुसपैट हमारे यहां लगातार बढ़ रही है। आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैट शादी कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे यहां जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं महिला, वह आदिवासी कोटे से लड़ती हैं और उसके पति मुसलमान हैं।

का विषय है। उन्होंने पाकुड़ जिले के तारानगर इलामी और दारापाड़ा में दंगे का मुद्दा उठाते हुए कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। दुबे ने कहा कि ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, सांसद ने स्वामी तक.

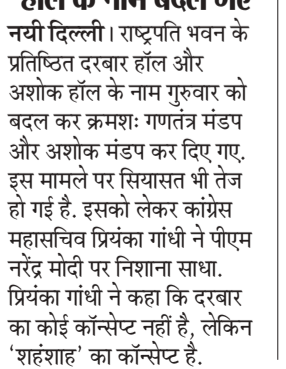
खैर अब लौटते हैं उत्तरप्रदेश में मौजूदा हालात पर. योगी जी न संघ में रहे हैं, ना ही भाजपा संगठन में. न उन्होंने संघ के लिए कुछ किया है, ना ही भाजपा के लिए. उनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा के थे और उनके शिष्य अवैद्यनाथ जी भी उसी के ध्वजवाहक थे. लेकिन ये दोनों राम मंदिर के लिए अड़े और लड़े. बाद में अवैद्यनाथ जी भाजपा से जुड़े, चुनाव लड़े और बाद में एक घटना के कारण आदित्यनाथ ने राजनीति में पदार्पण किया और

#### बांग्लादेशी कर रहे यहां की लड़कियों से शादी

कहा, मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार और जो पूरा संथाल परगना है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाइए. नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएंगे. एनआरसी लागू करिए. इसके पहले पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और इस कमेटी में टीएमसी के अधिक से अधिक सांसदों को शामिल करिए.

#### पेरिस ओलंपिक का आज रंगारंग उद्घाटन

पेरिस। पेरिस ओलंपिक शुक्रवार को सीन नदी पर ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। भारत भी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा होगा। उद्घाटन समारोह भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा और भारत में इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं होगा। सभी राष्ट्रों की पारंपरिक परेड पेरिस की सीन नदी के किनारे होगी। समारोह में, 100 नावों पर 10,000 एथलीट सीन के जरीए यात्रा करेंगे. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल, पेरिस परेड ऑफ नेशंस में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे. -पेज 10 भी देखें



बैजनाथ मिश्र  
वैद्यनाथ और अवैद्यनाथ  
के पूर्व शुभला अरुक्ता

#### प्रसंगवश

खैर अब लौटते हैं उत्तरप्रदेश में मौजूदा हालात पर. योगी जी न संघ में रहे हैं, ना ही भाजपा संगठन में. न उन्होंने संघ के लिए कुछ किया है, ना ही भाजपा के लिए. उनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा के थे और उनके शिष्य अवैद्यनाथ जी भी उसी के ध्वजवाहक थे. लेकिन ये दोनों राम मंदिर के लिए अड़े और लड़े. बाद में अवैद्यनाथ जी भाजपा से जुड़े, चुनाव लड़े और बाद में एक घटना के कारण आदित्यनाथ ने राजनीति में पदार्पण किया और

## विस का मॉनसून सत्र आज से, 29 को अनुपूरक बजट



विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में आयोजित बैठक में सीएम हेमंत सोरेन.

#### विशेष संवाददाता। रांची

हेमंत के तीसरी बार सीएम बनने के बाद विस का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. छह दिनों के कार्यदिवस वाले इस छोटे सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने गुरुवार को विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई.

बैठक में इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता एवं सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस की ओर से मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह और आजसू के लंबोदर महतो ने हिस्सा लिया. बैठक के बाद बातचीत में सीएम ने कहा कि सवाल की आते हैं, जवाब भी आते हैं. जैसा आसन का निर्देश होता है, उसके अनुसार सदन चलता है. जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के विधायक बैठक में नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वे लोग तो आए थे, मगर किस लिए आए, किस उद्देश्य के लिए आए, यह तो वही लोग बता सकते हैं. हेमंत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग पर कहा कि वे संसद देखें, झारखंड के बारे में अधिक चिंता न करें.

सत्र हंगामेदार होने की संभावना, भाजपा विभिन्न मुद्दों पर धेरगी : विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. भाजपा विभिन्न मसलों जैसे रोजगार, नौकरी, स्थानीय नीति, विधि व्यवस्था, बांग्लादेशी घुसपैट सहित अन्य मसलों पर सरकार को धेरगी. इधर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार कर रहा है.

#### स्पीकर ने की विधायकों की बैठक, भाजपा के लोग नहीं हुए शामिल

हेमंत ने कहा : भाजपा के कुछ लोग तो आए थे, मगर किस उद्देश्य से आए थे, वही बता सकते हैं.

सदन में किस दिन क्या होगी कार्यवाही  
26 जुलाई : शपथ ग्रहण अगर कोई हो तो, राज्यपाल सदन में प्रख्यापित अध्यादेशों को रखेंगे, शोक प्रस्ताव यदि हो तो  
27, 28 जुलाई : अवकाश  
29 जुलाई : प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश  
30 जुलाई : प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा  
31 जुलाई : राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य यदि हो, प्रश्नकाल  
01 अगस्त : प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य यदि हो  
2 अगस्त : राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य यदि हो, गैर सरकारी संकल्प









राज्यभर की खबरों के लिए स्कैन करें



www.lagatar.in

जमशेदपुर, शुक्रवार 26 जुलाई 2024 • श्रावण कृष्ण पक्ष 05 संवत् 2081 • पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹ 10 • वर्ष : 2, अंक : 108

आमंत्रण मूल्य : ₹ 3 मात्र

## कल्याण नगर-इंद्रा नगर बस्तियों के घरों को तोड़ने का मामला, 23 अगस्त को एनजीटी में होनी है सुनवाई एनजीटी में पूरी ताकत से लड़ेंगे बस्तीवासियों का मुकदमा : सरयू राय

वरीय संवाददाता | जमशेदपुर

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने उनसे जमशेदपुर के कल्याण नगर, इंद्रा नगर बस्तियों के घरों के टूटने की समस्या पर चर्चा की। उनके बीच इस समस्या के तमाम कानूनी पहलुओं पर विस्तार से वार्ता हुई। संजय उपाध्याय ने कहा कि वह बस्तीवासियों का मुकदमा एनजीटी में पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसके लिए

- दिल्ली में अधिवक्ता संजय उपाध्याय से मिले सरयू राय
- दोनों के बीच कानूनी पहलुओं पर विस्तार से हुई चर्चा
- बस्तीवासियों को वकालतनामा देना होगा



बस्तीवासियों को वकालतनामा देना होगा। सरयू राय ने उन्हें वकालतनामा लाकर देने का भरोसा दिया।

गौरतलब है कि आगामी 23 अगस्त 2024 को एनजीटी में इस

मामले को लेकर तारीख पड़ी है। श्री राय ने बताया कि दर्जन भर चुनिंदा बस्तीवासी वकालतनामा देकर अपना पक्ष रखेंगे और मांग करेंगे कि प्रशासन सही तरीके से सबे करे। अभी जो सबे

किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। यह एनजीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसमें कतिपय तथ्यों की अनदेखी हुई है। बस्तीवासी इस बारे में मुख्य सचिव को भी जापन देंगे। मुख्य सचिव को एनजीटी के सामने 23 अगस्त के पहले हलफनामा देना है। वह मांग करेंगे कि उनका पक्ष भी हलफनामा में रखा जाए। उनका पक्ष समाहित नहीं होगा तो वे वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय के माध्यम से अपना हलफनामा देंगे और एनजीटी से आग्रह करें कि उनके प्रस्ताव पर भी विचार करें।

### प्रशासन ने 150 घरों को तोड़ने का दिया है नोटिस

ज्ञात हो कि 13 जुलाई को जमशेदपुर अंचल कार्यालय की ओर से लगभग 150 घरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस में 14 दिनों का समय देते हुए सभी से जवाब मांगा गया। अर्थात् भवन तोड़ने की बात कही गई। विधायक सरयू राय सबसे पहले बस्ती पहुंचे तथा लोगों को आश्वस्त किया कि घर नहीं टूटेंगे। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त से भी बात की। दूसरे दिन पूरे सांसद डॉ.

अजय कुमार अपने समर्थकों के साथ कल्याणनगर तथा इंद्रानगर पहुंचे। मामला गरमाता देख भाजपा सांसद विद्युत वर्णन महतो ने बस्ती का दौरा करने के बाद उपायुक्त के साथ बैठक कर मामले की जानकारी ली। बाद में सरयू राय ने इसपर तंज भी कसा कि बयानबाजी और झापान से यह मसला हल नहीं होगा। कानूनी लड़ाई से ही हल निकलेगा और इसके लिए सभी दलों से एक मंच पर आने की अपील भी की थी।

## जेपीएस की फाउंडर प्रिंसिपल ललिता सरिन का निधन



संवाददाता | जमशेदपुर

शहर की जानीमानी शिक्षाविद ललिता सरिन का गुरुवार को सक्रिंत हाउस स्थित उनके घर में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। उन्हें एक वर्ष कैंसर था। उनका इलाज चल रहा था। स्वर्गीय ललिता सरिन बारीडीह स्थित

जमशेदपुर पब्लिक स्कूल (जेपीएस) की फाउंडर प्रिंसिपल रह चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 1988 में इस स्कूल में प्रिंसिपल का पदभार लिया था। वे करीब 20 वर्षों तक इस स्कूल में प्रिंसिपल रहते हुए स्कूल को ऊंचाई पर ले गईं। जेपीएस से रिटायर होने के बाद उन्होंने मानगो के पारडीह में माउंट जी लियेटो स्कूल में डायरेक्टर का पदभार संभाला। स्वर्गीय ललिता सरिन की भाभी शुचिता सरिन ने बताया कि उनके भतीजे व सगे-संबंधियों को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

### ब्रीफ खबर

आज कदमा व मानगो में 3 घंटे नहीं आएगी बिजली

जमशेदपुर। झारखंड बिजली विवरण निगम की ओर से शुक्रवार को डिमना और उलियान पावर सब स्टेशन में मरम्मत कार्य चलाया जाएगा। जिसके चलते तीन घंटे तक बिजली सेवा प्रभावित रहेगी। सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक कदमा के सतीथाट रोड, मरीन ड्राइव, उलियान मेन रोड, भाटिया बस्ती, अनिल सुर पथ, एनएच 33 पीपला, भिलाई पहाड़ी, हीरा चुनी, नरगा, गुर्मा क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सप्लाइ बाधित रहेगी।

साकची पेनार रोड में खाली कराया बेसमेंट

जमशेदपुर। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएनएसी की ओर से चलाए जा रहे बेसमेंट अतिक्रमण अभियान बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी चला। बुधवार को जहां से अतिक्रमण हटाया गया था। वहां शेष ढांचा तोड़ने के लिए टीम पहुंची तथा उसे खाली कराया। वहीं साकची के पेनार रोड स्थित होल्डिंग नंबर 76 के खिन्नाई कारवाई शुरू की गई। इसी दौरान भवन के मालिकों ने खुद ही अनधिकृत हिस्से को तोड़ने की को हामी भरी। उसे समय दे दिया गया।

कैरम सलेक्शन ट्रायल में 250 छात्रों ने लिया हिस्सा

जमशेदपुर। सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल बालिचेली की मेजबानी में सीआईएससीई बोर्ड के जमशेदपुर जेन के विद्यालयों का दो दिवसीय पांचवीं ज्यूनियर कैरम (बोर्ड) सलेक्शन ट्रायल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। सलेक्शन ट्रायल प्रतियोगिता में शहर के सीआईएससीई बोर्ड के विद्यालयों के 250 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। पहले दिन बालक वर्ग के तीनों कैटेगरी में लीग मैच हुए।

भाजपा का नशे के कारोबार के खिलाफ प्रदर्शन

जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत सीतारामडंडा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। बृहस्पतिवार को भाजपा सीतारामडंडा मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीतारामडंडा थाना पर प्रदर्शन किया तथा थाना प्रभारी को जापन सौंपकर नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे के अंधकार से दूर करने की मांग की।

पूर्व सांसद डॉ. अजय ने वलाया जनसंपर्क अभियान

जमशेदपुर। पूर्व सांसद सह कांग्रेस का वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकाक ती तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए, मौके पर डॉ. अजय कुमार ने कहा कि वे क्षिण वादा नहीं करते बल्कि लोगों की जनसमस्याओं का समाधान भी करते हैं। उन्होंने युवाओं का होसला बढ़ाते हुए उन्हें खूब पढ़ने और खेलने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ कर अपने करियर पर ध्यान दे युवा तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा।

## कपाली में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या का मामला पुलिस ने दो को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी



आमेर अली की फाइल फोटो

वरीय संवाददाता | जमशेदपुर

मानगो से सटे कपाली थाना क्षेत्र के डोबो-पुडिसिली मुख्य सड़क किनारे बुधवार की रात हुई आमेर अली (23) की हत्या मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए युवक आमेर अली के साथ ही थे। हालांकि पुलिस को वहां अन्य लड़कों के भी होने की संभावना है। पुलिस युवकों से पूछताछ के आधार पर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ। जिसके बाद आमेर अली की धारदार हथियार व पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शराब की बोतल तथा प्लास्टिक शराब भी बरामद किया है। इससे संदेह लगाया जा रहा है कि शराब पीने के बाद आमेर अली की हत्या हुई होगी।

कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि आमेर अली का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जिसके कारण उसका कपाली आना-जाना का समय दिया था। पैसा नहीं देने पर 19 जुलाई को आए तथा मारपीट की। दबंगों की हरकतों से सुचिता देवी का पूरा परिवार दहशत में है। सुचिता का आरोप है कि उलीडीह पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि इलाके में उनका वर्चस्व है। अगर जमीन की खरीद-बिक्री कोई करता है, तो उन्हें रंगदारी की रकम देनी पड़ती है।

- घटनास्थल से मिली थी शराब की बोतल
- हर बिंदू पर जांच कर रही है पुलिस

रहा है। परिवार में उसका पिता उमर अली, छोटा भाई रहमत अली तथा बहन है। एक माह पहले वह आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में रहने के लिए चला गया। हालांकि उसका कपाली आना-जाना लगा रहा। घटना के दिन भी वह पहले अपने घर आया। उसके बाद दोस्तों से मिलने की बात कहकर चला गया। उसके बाद उसकी हत्या की खबर परिजनों को मिली। परिजन भागे-भागे घटनास्थल पर पहुंचे। अंधेरा होने के कारण थार्ल एवं गाड़ी की लाइट में घटनास्थल से पुलिस ने खून से सना पत्थर, समीप पड़ा शराब की बोतल एवं अन्य सिद्ध चीज बरामद की।

## उलीडीह की महिला से मांगी 50 हजार रंगदारी



एसएसपी के यहां शिकायत लेकर पहुंची महिला एवं परिवार के सदस्य

जमशेदपुर। उलीडीह ओपी अंतर्गत शांतिनगर की रहने वाली सुचिता देवी ने क्षेत्र के दबंगों ने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर सुचिता देवी एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। घटना 19 जुलाई की है। घटना के बाद महिला परिवार के सदस्यों के साथ उलीडीह थाना गई तथा शिकायत की। लेकिन पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अंत में महिला परिवार के सदस्यों के साथ बृहस्पतिवार को एसएसपी से मिलने पहुंची। महिला ने बताया कि उलीडीह के रहने वाले डब्लू सिंह, शक्तिनाथ सिंह, कुश वर्मा, रंजीत गिरि, दीपक, कंचन सिंह और किशोर रजक उसके घर आते हैं तथा गाली गलौज करते हैं। रंगदारी में 50 हजार रुपये की मांग की। सभी 19 जून को भी घर पर आए थे तथा एक माह का समय दिया था। पैसा नहीं देने पर 19 जुलाई को आए तथा मारपीट की। दबंगों की हरकतों से सुचिता देवी का पूरा परिवार दहशत में है। सुचिता का आरोप है कि उलीडीह पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि इलाके में उनका वर्चस्व है। अगर जमीन की खरीद-बिक्री कोई करता है, तो उन्हें रंगदारी की रकम देनी पड़ती है।

## तैयारी लोयोला स्कूल पहुंचकर डीसी-एसएसपी ने मतदाता सूची में अपना नाम जांचा वोटर लिस्ट में छूटे हुए मतदाताओं का नाम 9 अगस्त तक होगा दर्ज

- आवासीय कालोनी पहुंचकर अधिकारियों ने आम लोगों से की बात

वरीय संवाददाता | जमशेदपुर

जिले के मतदान केंद्रों पर बृहस्पतिवार को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्व से घोषित रनाम जांचोहर सोशल मीडिया अभियान भी चला। उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी कोशल किशोर, डीडीसी मनीष कुमार समेत सभी वरीय पदाधिकारियों ने अपने-अपने बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचा तथा उसे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया। मतदान केंद्र के बाद अधिकारी अलग-अलग आवासीय सोसायटी में पहुंचकर आम लोगों से मिले तथा उनके नाम की मतदाता सूची में जांच करवाई। इससे पहले सुबह डीसी, एसएसपी, डीडीसी समेत अन्य



वोटर लिस्ट में अपना नाम देखते उपायुक्त अनन्य मित्तल।

अधिकारी लोयोला स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहां मौजूद बीएलओ से मतदाता सूची लेकर अपने नाम की जांच की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभी बीएलओ को कहा कि शत प्रतिशत मतदान के लिए



राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते उपायुक्त।

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाली गतिविधियों की उन्हें जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों में

## सुरदा माइंस के एनवायरमेंट विलियर्स का मिला भरोसा केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद विद्युत वर्णन महतो

संवाददाता | मुसाबनी

सांसद विद्युत वर्णन महतो ने गुरुवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर सुरदा माइंस के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस यथाशीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। विगत चार वर्षों से सुरदा माइंस वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बंद पड़ी है। जिसके कारण मुसाबनी का कंसट्रेटर संयंत्र भी बंद पड़ा है और हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हैं। सांसद ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को जापन सौंप कर कहा कि सुरदा माइंस के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया जा चुका है और जैसे ही एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाता है यह माइंस चालू हो जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने सांसद विद्युत वर्णन महतो को बताया कि संबंधित कागजात राज्य सरकार द्वारा अत्यंत विलंब से उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। उन्होंने सांसद को आश्वस्त



किया कि अब इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होगा। आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे यथाशीघ्र केंद्रीय सचिव के पास इसे प्रेषित करेंगे। सांसद ने इसके पश्चात वन एवं पर्यावरण विभाग के केंद्रीय सचिव लीना नंदन से भी मुलाकात की और जापन सौंपा। केंद्रीय सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि सारी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर दी जायेगी। इससे राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया जायेगा। सांसद ने यह उम्मीद व्यक्त किया है की आने वाले निरूक्त भविष्य में सुरदा माइंस के उत्पादन शुरू होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।



# 'हिट एंड रन' के इस मामले में पांच दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कार की चपेट में आने से घायल हुए युवक की मौत

संवाददाता। हजारीबाग

कार की चपेट में आने से घायल हुए दो युवकों में एक की बृहस्पतिवार को रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मृतक शुभम के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ सदर थाना पहुंच कर आरोपी गाड़ी मालिक और चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की।

परिजनों ने 'हिट एंड रन' के इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के घर गई लेकिन वहां से आरोपी फरार था। इस संबंध में सदर पुलिस ने बताया कि रविवार की रात शहर के आनंद

## खास बातें

- कार मालिक और चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस
- परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई न्याय की गुहार



बता दें कि शहर के आनंद चौक पर बोते रविवार की रात करीब 9:30 बजे 'हिट एंड रन' की घटना हुई थी। इसमें एक कार ने पैदल चल रहे दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक शुभम की गुरुवार को रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान झंडा चौक स्थित महावीर स्त्रिय निवासी तपेश्वर गुप्ता के पुत्र के रूप में हुई। वहीं घायल युवक प्रेम जैन रांची के वेदांत अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। इस संबंध में परिजन रवि कुमार ने बताया कि रविवार रात 9:30 बजे शहर के ही दो युवक कार लेकर जा रहे थे। चालक डेज़र ड्राइविंग कर रहा था। चालक पैदल जा रहे शुभम कुमार और प्रेम जैन को जोरदार टक्कर मारते हुए अपनी मारुति कार लेकर भाग गया। कार में बैठे दोनों युवक शराब के नशे में थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को सदर अस्पताल भेज

दिया और कार को पकड़ कर जन्न कर लिया। तलाशी में कार से शराब की बोतल और प्लेट पुलिस को मिली है। उन्होंने बताया कि घटना के पांच दिन बाद तक भी पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजनों ने यह भी बताया कि शहर में पिछले एक महीने से डेज़र ड्राइविंग, हेलमेट एवं अन्य कागजात की पुलिस जांच कर रही है। इसके बावजूद शहर में इस तरह की घटना घट रही है। पुलिस मौन धारण कर रखी है। ऐसे में पुलिस पर से विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है।

# नाम जांचो अभियान में डीसी ने लिया हिस्सा, सूची में अपने नाम की जांच की

संवाददाता। रामगढ़

मतदाताओं को जागरूक करने तथा प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित करने को लेकर बृहस्पतिवार को संचालित नाम जांच अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार ने उल्लिखित उच्च विद्यालय छत्तरमांडू में मतदान केंद्र संख्या 107 पर जांच कर मतदाता सूची में अपने नाम की जांच की। साथ ही उन्होंने सभी से प्रत्येक निर्वाचन में अपने मतदाता का प्रयोग करने तथा मतदान केंद्र, वोटर हेल्पलाइन एवं सहित अन्य माध्यमों से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने की अपील की। गौरतलब हो कि मतदाता



मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करते उपायुक्त चंदन कुमार।

सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी आशीष

गंगवार, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने भी नाम जांच अभियान में हिस्सा लिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।

## ब्रीफ खबरें

### एक लाख अरसी हजार ले उड़े उच्चके

विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है। निरंतर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। न तो अपराधी पकड़ में आ रहे हैं और न ही घटनाओं पर विराम लग पा रहा है। गुरुवार को दोपहर विष्णुगढ़ के अखाड़ा चौक में अपराधियों ने एक और आपराधिक घटना को अंजाम दिया। विष्णुगढ़ के चंद्रिका साव इसके शिकार हुए। उन्होंने एसबीआई की विष्णुगढ़ शाखा से एक लाख अरसी हजार रुपये निकाले। रुपये झोले में रखे और अपनी साइकिल के हैंडल में लटकाकर अखाड़ा चौक स्थित एक दुकान में घुस गए। बाहर रुपये वाले झोले को उसी तरह साइकिल के हैंडल में लटकाकर उन्होंने छोड़ दिया। इसी बीच एक अपराधी आया तथा झोले से रुपये निकाल कर अपने साथी की आंखें बाइक में सवार होकर फरार हो गया।

### महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट खर्च उठाएगी

चौपारण। हिंदू धर्म में सावन के महीने को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती के लिए समर्पित होता है। कई शिवभक्त पैसे के अभाव के कारण चाहकर भी कांवड यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर शिवभक्त भी इस साल बाबा वैद्यनाथ धाम कांवड लेकर जा सकत हैं, जिनका पूरा खर्च महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट उठाएगी। इस संबंध में महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सह उतरी छोटानापुर प्रमंडलीय प्रभारी भाजयुगो अविनाश आर्या ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर जो शिव भक्त कांवड यात्रा करना चाहते हैं उन्हें महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क यात्रा करवाएगी। ऐसे शिवभक्त 9060610777, 8294975482 पर संपर्क कर सकते हैं।

### बजरंग दल करेगा हिंदू महापंचायत

हजारीबाग। धर्म विरोधी घटना को लेकर बजरंग दल ने हिंदू महापंचायत का आयोजन किया है। बड़कागांव प्रखंड के करेडारी क्षेत्र के समस्त हिंदू जनमानस और सनातन धर्म प्रेमियों को बजरंग दल ने सूचित किया है कि आगामी दिनों में क्षेत्र में घट रही धर्म विरोधी घटनाओं के संबंध में हिंदू महापंचायत का आयोजन बड़कागांव कुशवाहा धर्मशाला गुरुद्वी में शुक्रवार को 11 बजे दिन में रखा गया है। बजरंग दल द्वारा क्षेत्र के सभी हिंदू जनमानस को सादर आमंत्रित किया गया है। बजरंग दल की ओर से प्रो. जिलान प्रमुख संजय चौबे ने हिंदू जनमानस से महापंचायत में आने का निवेदन किया गया है।

# सरकारी योजनाओं के काम मशीन से कराकर टेकेदार और बिचौलिया हो रहे मालामाल मजदूर पलायन करने को मजबूर

मामला संज्ञान में लाए जाने के बादजुद अधिकारियों का पलायन रोकने व स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की ओर ध्यान नहीं

प्रमोद उपाध्याय। हजारीबाग

एक तरफ जहां सरकार मनरेगा जैसी योजना चला रही है। वहीं दूसरी तरफ जिले में रोजगार नहीं मिल पाने के कारण स्थानीय मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दो दिन पहले पेलावल से तीन दर्जन मजदूर अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्य चले गए। बता दें कि शुभम संदेश ने एक माह पहले मजदूरों की इस पीड़ा को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे जिले के मजदूर रोजगार नहीं मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं।

मजदूरों ने यह भी बताया था कि निजी मकान में थोड़ा बहुत काम चलता है, जिसमें मजदूरों कभी रोजगार मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। उसमें भी टेकेदार मजदूरों का रेट अपने हिसाब से तय करता है। जरूरतमंद मजदूर कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेकेदार कभी पैसा देता है तो कभी हप्ता दिन तक नहीं देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हफ्तों रोजगार नहीं मिलता है। मजदूर रोजगार की आस में गांव से शहर आते हैं और निराशा होकर खाली हाथ वापस घर चले जाते हैं। अपनी खबर के साथ शुभम संदेश इस मामले को सरकार और जिले के अधिकारियों के संज्ञान में लाने का



पूव में मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रकाशित की गई खबर और पलायन करने वाले मजदूर।

## शुभम संदेश की खबर पर हरकत में आया फॉरेस्ट विभाग

वहीं दूसरी ओर बड़कागांव के उरीभारी के दो दर्जन मजदूरों को साल भर पहले फॉरेस्ट विभाग ने हाजिरी पर काम करवाया था, लेकिन जब मजदूरों की मजदूरी देने की बाड़ी आदि तो फॉरेस्ट विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। वह मजदूरी देने में टालमटोल करने लगा, आश्रवासन देने लगा। एक साल बाद पीड़ित मजदूर फॉरेस्ट ऑफिस



पूव में मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रकाशित की गई खबर और पलायन करने वाले मजदूर।

## शुभम संदेश की खबर पर हरकत में आया फॉरेस्ट विभाग

पहुंचे और मजदूरी का भुगतान करने की मांग की, लेकिन एक बार फिर आश्रवासन ही मिला। इसके बाद मजदूरों ने शुभम संदेश से गुहार लगाई। शुभम संदेश ने प्रमुखता के साथ मजदूरों की पीड़ा सरकार तक पहुंचाई, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग हरकत में आया और मजदूरों को थोड़ा बहुत पैसा देकर नजर बंद कर दिया।

काम किया था। लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। यथार्थतः कायम रहने की वजह से दाने-दाने को मोहताज हो गए शहर के पेलावल रोमी से लगभग तीन दर्जन मजदूर अपने परिवार से दूर दूसरे राज्य रोजगार की तलाश में निकल गए। इस दौरान मजदूरों के परिजन भी

लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने यह भी बताया कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अगर हजारीबाग में मजदूरों को रोजगार मिलता तो यहां काम के साथ-साथ उन्हें जनप्रतिनिधि भी चुनने का मौका मिलता, लेकिन इस स्थिति में वे घर परिवार को देखेंगे या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। बरसात में लोग घर आते हैं, मजदूर बाहर जाने को मजबूर : इस संबंध में पेलावल विकास मंच के स्थापक सह अध्यक्ष एम हक ने बताया कि राज्य सरकार तरह-तरह की रोजगार योजना ला रही है, लेकिन किसी का लाभ मजदूरों को नहीं मिलता, बल्कि टेकेदार और बिचौलिया मिलकर अधिकांश योजनाओं की राशि हजम कर जाते हैं। यही कारण है कि मजदूर यहां से दूसरे राज्य के लिए पलायन

कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में इन दिनों रोजगार मिला करता था, लेकिन वर्तमान में यहां न बालू मिल रहा है और न ही छरी है। इस वजह से निजी मकान में काम नहीं चल रहा है। यहां तक बिल्डिंग मैटेरियल के अभाव में टेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया है। इसके साथ ही बरसात का महीना है। ऐसे में मजदूर अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य चले गए हैं। बरसात में उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि आमतौर पर बरसात के महीने में लोग बाहर से अपने घर आते हैं, लेकिन हजारीबाग के मजदूर बरसात में घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक महीने पहले भी लगभग 15 मजदूर इसी जगह से दूसरे राज्य जा चुके हैं।

# डीसी ने किया मतदान केंद्रों का दौरा

संवाददाता। रामगढ़

मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों को लेकर गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने 22 बड़कागांव एवं 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने छत्तरमांडू क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 109, 110, 111, 112, छावनी कन्या मध्य विद्यालय सुभाष चौक रामगढ़ में मतदान केंद्र संख्या 1, 2, 3 एवं 22 बड़कागांव अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 443 का निरीक्षण कर द्वितीय मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को हुए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने सभी बीएलओ सहित अन्य कर्मियों को उनके उनके में प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित होना सुनिश्चित करने, लोगों को



मतदान केंद्र पहुंचे उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार।

मतदाता सूची में अपना नाम जांच करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्धारित विशेष शिविर दिवस 27 जुलाई शनिवार, 28 जुलाई रविवार, 3 अगस्त शनिवार

# ग्रामीणों की जमीन बचाने के लिए कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह उतरे मैदान में महिलाओं से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग

संवाददाता। हजारीबाग

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह सदर प्रखंड के सखिया पंचायत के बेलामुडवार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर एक जमीन संबंधित शिकायत को लेकर हजारीबाग के एसडीपीओ और डीआईजी से मुलाकात की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पूर्वजों से दान में मिले सामूहिक जमीन पर अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सामूहिक जमीन, खता न. 1 और प्लॉट नम्बर 103, को स्थानीय जमीन दलाल मनोज साव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जबरन कब्जा कर लिया है। मनोज साव इस जमीन पर डस्ट गिराकर और बाड़डू करने के उद्देश्य से काम कर रहा था, जिसके खिलाफ गांव की महिलाओं ने आवाज उठाई। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के



सदर प्रखंड के सखिया पंचायत के बेलामुडवार गांव पहुंचे मुन्ना सिंह।

अनुसार उनके विरोध करने पर मनोज साव ने उनके साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और छेड़छाानी की। जब महिलाओं ने अपने बचाव के लिए धमकीयों को बुलाया, तो भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस दौरान मनोज साव भागने की कोशिश में गिरते-पड़ते भागा और ग्रामीणों को धमकी दी कि वह सभी को झूठे आरोप में फंसवा देगा, यह दावा करते

व्यक्त करते हुए कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव की सामूहिक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में उच्च पदाधिकारियों के द्वारा हस्तछेप किया जाए।" मुन्ना ने कहा कि ग्रामीणों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और कांग्रेस पार्टी उनके हक की लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ है। मौके पर राहुल यादव, अनिल यादव, राजेश यादव, धनराम यादव, भरत यादव, विनोद यादव, अजुन यादव, सन्तु यादव, धर्मन्द्र यादव, पप्पू यादव, संजय यादव, संतोष यादव, नरेश यादव, विरेंद्र यादव लाल यादव सुधीर यादव, किशोर कुमार यादव, किशोर यादव, कारु यादव, अशोक यादव, महेंद्र यादव, रमेश्वर यादव आदि मौजूद थे।

# प्रक्रिया मृतक को न्याय दिलाए जाने को लेकर जांच की जा रही है : अजय कुमार एएसआई राहुल की मौत की जांच करने पहुंचे एसपी

संवाददाता। रामगढ़

बरकाकाना ओपी क्षेत्र के बंजारी मंदिर के समीप ड्यूटी में तैनात राहुल कुमार सिंह की मौत की घटना नुल पकड़ने लगी है। राहुल कुमार सिंह की हुई मौत की जांच करने रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंजारी मंदिर चेक पोस्ट पहुंचे। यहां उन्होंने बंजारी धर्मशाला में पुजारी राजेंद्र उपाध्याय व अन्य लोगों से पूछताछ की। बता दें कि 21 जुलाई को ड्यूटी पर तैनात ट्रेफिक पुलिस के एएसआई राहुल कुमार सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार पर कई



एएसआई की मौत की जांच करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक व अन्य।

गंभीर आरोप लगाया गया था। इसके बाद रामगढ़ जिला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार को स्थानांतरित करते हुए मुख्यालय बुला लिया गया है, जबकि तत्कालीन

रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को पुलिस महानिदेशक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम रिस्स में

किया गया, जहां मौत का कारण जहर बताया गया, बताया जाता है कि तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा अनिकेत नामक युवक को पकड़ कर थाना लाया गया था। अनिकेत द्वारा 21

फरवरी को पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली गई, जबकि मृतक राहुल कुमार सिंह एक अन्य चोरी के मामले के अनुसंधान पदाधिकारी थे, जहस पर थाना प्रभारी अजय कुमार साहू द्वारा पर प्रार्थित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जांच किए जाने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर बताया कि मृतक को न्याय दिलाए जाने को लेकर जांच की जा रही है ताकि मृतक को न्याय मिल सके। मौके पर मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, पतरातु पुलिस उपाधीक्षक, पुअनि मुन्ना सिंह, पुअनि अजुन उरांव, पुअनि अखतर अली सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

# 65 प्रतिशत पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण देना अन्यायपूर्ण : मेहता

कांग्रेस नेता ने कहा- इंडिया गठबंधन के लोग इस मुद्दे को जोर-जोर से उठाए

संवाददाता। हजारीबाग

कांग्रेस नेता डॉ. आरसी प्रसाद मेहता ने कहा कि संपूर्ण भारत में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मंडल कमीशन के संयोजक पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह द्वारा मिला है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का समर्थन विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बिल झारखंड कैबिनेट में पास किया गया, परंतु राज्यपाल ने बिल को रोक कर अन्याय किया है। हमारे प्रधानमंत्री

पिछड़ों के नाम पर प्रधानमंत्री बने, पिछड़े के नाम पर थोक में वोट मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने यदि मोदी चाहते तो झारखंड के लोगों के साथ 27 प्रतिशत आरक्षण देकर न्याय कर सकते थे जो नहीं किया, परंतु मोदी ने आर्थिक रूप से पिछड़े, नौ लाख से कम आय वाले वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जो प्रशंसनीय है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ, ज्ञातव्य हो कि संपूर्ण भारत में सर्वण अगड़ों की आबादी 10 प्रतिशत से कम है, परंतु झारखंड के 65 प्रतिशत पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण देना अन्यायपूर्ण है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी और मोदी ने पिछड़ों को प्रताड़ित करने का काम किया है। हम तमाम

पिछड़ों से आह्वान करते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को तब तक उठाते रहें जब तक मुख्यमंत्री अपनी भूल का सुधार न करें। विधानसभा चुनाव में सभी इंडिया गठबंधन के लोग इस मुद्दे को जोर-जोर से उठाएं और अपने हक की मांग करें। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा प्रवुद्ध ओबीसी व्यक्तियों की एक बैठक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष अलिताप साहू की अध्यक्षता में प्रेस क्लब रांची में की थी। सभा में झारखंड कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजाद अनवर, केसव महतो कल्लेश एवं हजारों वरिष्ठ ओबीसी कांग्रेसी उपस्थित थे।







## उपेक्षित राज्यों में विक्षोभ

बजट भाषण में इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं के तल्ख तेंवर से खुश केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सार्थक चर्चा नहीं कर रहा है. दस सालों के बाद लोकसभा का समीकरण बदला हुआ है, जिसमें एक ओर वास्तविक अर्थों वाली गठबंधन सरकार को मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर सदन के बाहर भी दिख रहा है. बजट प्रावधानों में गैर-भाजपा शासित राज्यों की उपेक्षा का असर नीति आयोग की बैठक पर भी पड़ने जा रहा है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बजट में झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया तो कहा है कि विशेष पैकेज केंद्र सरकार वैश्याखियों को दे, लेकिन वह झारखंड को उसका बकाया चुका दे. झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया है. गैर भाजपा शासित पांच राज्यों में एलान किया है कि वे बजटीय उपेक्षा के प्रति अपना विरोध जताते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था. इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेताओं ने इसे 'सरकार बचाओ बजट' तो किसी ने 'भेदभावपूर्ण' बजट करार दिया. इसके बाद कांग्रेस ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का एलान किया था. नीति आयोग की बैठक में कनाटक, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भाग नहीं लेंगे. पंजाब सरकार ने भी नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का निर्णय किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट के दौरान तेलंगाना के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है. इसके अलावा राज्य की बकाया धनराशि भी जारी नहीं की गई. इसके विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है. तेलंगाना विधानसभा में दिन भर चली बहस के बाद केंद्रीय बजट में तेलंगाना के प्रति केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बजट में बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया है, लेकिन वे नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दस सालों में अनेक अवसरों पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगात्मक संघवाद की वकालत करते रहे हैं. लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि संघात्मकता की मूल भावना केवल कागजी बन कर रह जाती है. इस तथ्य को गंभीरता से समझने और अमूल में लाने की जरूरत है कि देश के सभी राज्यों के लिए समान अवसर का माहौल बनाना चाहिए. देश के ज्यादातर राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. केंद्र की मदद की जरूरत सभी राज्यों को है. इसलिए बजट आबंटन में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना जरूरी है.

### झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया है. गैर भाजपा शासित पांच राज्यों में एलान किया है कि वे बजटीय उपेक्षा के प्रति अपना विरोध जताते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.

झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया है. गैर भाजपा शासित पांच राज्यों में एलान किया है कि वे बजटीय उपेक्षा के प्रति अपना विरोध जताते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.

### सुभाषित

प्ररोऽपि हितवान् बन्धुः बन्धुरप्यहितः परः। अहितो देहजो व्याधिः हितमारण्यमोघधम्॥

बीमारियां हमारे शरीर के भीतर रहते हुए भी हमारा बुरा करती है और औषधियां (जड़ी-बूटियां) हमसे दूर पेड़-पौधों में रहकर भी हमारा भला करती हैं. इसी प्रकार, जिनसे हमारा रक्त का सम्बन्ध न हो, किन्तु वे हमारा हित करें तो वे अपने हितों से ही और यदि रिश्तेदार होकर भी कोई हमारा अहित करे तो वह पराया होता है.

# सामाजिक सुरक्षा का विस्तार जरूरी

भारत एक लोकतांत्रिक व कल्याणकारी राज्य है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए. निःसंदेह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ठेकी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इसे विस्तार देने की जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय ऐसी सभी सेवाओं, साधनों और सुविधाओं से है, जो नागरिकों को दी जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है. सामाजिक सुरक्षा श्रम कल्याण का एक मुख्य संघटक है और उसे निरंतर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाता है. सामाजिक सुरक्षा वैश्वीकरण और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से उपजी चुनौतियों से निपटने में अधिक सकारात्मक रवैए के निर्माण में सहायता प्रदान करती है. सामाजिक सुरक्षा में यह परिकल्पना की जाती है कि नागरिकों को सभी प्रकार के सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जाएगी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरित में अनावश्यक मुश्किलें उत्पन्न करती हैं. यह सच्चाई है कि कमगारों के पास बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, रोग और बेरोजगार आदि के कारण उत्पन्न जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होता है और संकट के समय में उनकी सहायता करने के लिए जीविका का वैकल्पिक साधन का अभाव होता है. इसलिए कमगारों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य का दायित्व है. 19 वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे. उनका मुख्य काम शांति व व्यवस्था कायम रखना था. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के कार्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के जिम्मे छोड़ रखे थे. लेकिन धीरे-धीरे राज्य के स्वभाव में बुनियादी बदलाव आया और उसकी प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था शामिल पर हो गयी. लॉयड जार्ज के प्रथम मंत्रित्व काल में इंग्लैंड की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत सामाजिक बीमा चालू किया, जिसके तहत बूढ़े, अवाकाश प्राप्त व्यक्ति, विधवाएं और बेरोजगार लाभ उठाते हैं. इस योजना के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को दूध देने, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को दूध और विशेष भोजन देने, निःशुल्क डॉक्टर सहायता और निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अति छात्रवृत्तियों की व्यवस्था का भी गयी है. गौर करें तो संपूर्ण यूरोपीय देशों में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लागू है. संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जनता को लाभ पहुंचाने संबंधी विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चालू हैं. भारतीय संदर्भ में

## समाज

### अरविंद जयतिलक

भारत एक लोकतांत्रिक व कल्याणकारी राज्य है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए. निःसंदेह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ठेकी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इसे विस्तार देने की जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय ऐसी सभी सेवाओं, साधनों और सुविधाओं से है, जो नागरिकों को दी जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है. सामाजिक सुरक्षा श्रम कल्याण का एक मुख्य संघटक है और उसे निरंतर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाता है. सामाजिक सुरक्षा वैश्वीकरण और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से उपजी चुनौतियों से निपटने में अधिक सकारात्मक रवैए के निर्माण में सहायता प्रदान करती है. सामाजिक सुरक्षा में यह परिकल्पना की जाती है कि नागरिकों को सभी प्रकार के सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जाएगी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरित में अनावश्यक मुश्किलें उत्पन्न करती हैं. यह सच्चाई है कि कमगारों के पास बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, रोग और बेरोजगार आदि के कारण उत्पन्न जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होता है और संकट के समय में उनकी सहायता करने के लिए जीविका का वैकल्पिक साधन का अभाव होता है. इसलिए कमगारों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य का दायित्व है. 19 वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे. उनका मुख्य काम शांति व व्यवस्था कायम रखना था. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के कार्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के जिम्मे छोड़ रखे थे. लेकिन धीरे-धीरे राज्य के स्वभाव में बुनियादी बदलाव आया और उसकी प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था शामिल पर हो गयी. लॉयड जार्ज के प्रथम मंत्रित्व काल में इंग्लैंड की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत सामाजिक बीमा चालू किया, जिसके तहत बूढ़े, अवाकाश प्राप्त व्यक्ति, विधवाएं और बेरोजगार लाभ उठाते हैं. इस योजना के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को दूध देने, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को दूध और विशेष भोजन देने, निःशुल्क डॉक्टर सहायता और निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अति छात्रवृत्तियों की व्यवस्था का भी गयी है. गौर करें तो संपूर्ण यूरोपीय देशों में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लागू है. संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जनता को लाभ पहुंचाने संबंधी विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चालू हैं. भारतीय संदर्भ में

## मीडिया में अन्त्यर

# पूँजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाने वाला बजट

केंद्रीय बजट में एक अच्छी बात रही पूँजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाना. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने कहा कि चुनिंदा वित्तीय परिस्थितियों पर अल्पावधि का पूँजीगत लाभ कर 20 फीसदी की दर से लगाया जाएगा जबकि पहले यह 15 फीसदी की दर से लगाया जाता था. अन्य सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिस्थितियों पर उसी दर से कर लगेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि शेयर बाजार में अल्पावधि में होने वाले लाभ पर 20 फीसदी की दर से कर चुकता करना होगा. इसके अलावा सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिस्थितियों पर होने वाले दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 फीसदी की दर से कर लगेगा. सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर की दर 10 फीसदी थी. लंबी अवधि के कर अल्पावधि के कर के बीच के अंतर को बढ़ाने वाले कारणों में से एक पूँजी बाजार में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना भी हो सकता है. खासतौर पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में निवेशकों को कम आय वाली श्रेणी की बात करें तो वित्त मंत्री ने पूँजीगत लाभ के मामले में पर्याप्त कर की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है. सूचीबद्ध वित्तीय परिस्थितियों को अगर एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखा गया तो उन्हें दीर्घकालिक माना जाएगा. गैर सूचीबद्ध वित्तीय और गैर वित्तीय परिस्थितियों के मामले में

उन्हें दो वर्ष तक धारण करने पर ही उन्हें दीर्घकालिक माना जाएगा. गैर सूचीबद्ध बॉन्ड और डिबेंचर और डेट म्यूचुअल फंड पर लागू दर से ही पूँजीगत लाभ कर लगेगा. बजट के दिन सूचीबद्ध शेयरों पर पूँजीगत लाभ कर बढ़ाने की घोषणा ने शेयर बाजारों को प्रभावित किया. इसके चलते कीमतों में लोच के कारण कुछ लोग और भी जगह और शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि दोनों शब्दों के बीच काफी अंतर है. और संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका मतलब है किनारा, किसी नियत स्थान के अतिरिक्त विस्तार जिसे दाहिना बायां, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम आदि शब्दों से निचयित करते हैं. तरफ, दिशा. पक्ष. जैसे यह उनकी ओर का आदर्मी है. हम आपकी ओर से बहुत कुछ कहेंगे. मजेदार बात यह है कि ओर संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अगर ओर कहलते कोई संख्यावाचक शब्द आता है, तब इसका व्यवहार पुल्लिंग की तरह होता है. जैसे घर के चारों ओर, उसके दोनों ओर. वैसे ओर संज्ञा पुल्लिंग रूप में भी व्यवहार में आता है, जिसका मतलब है अंत, सिरा, छोर, किनारा, आदि, आरंभ. कहते हैं कि उसकी बातों का न कोई ओर है न छोर. ओर आना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है नाश का समय आना. उदाहरण के लिए हंसता ठाकुर, खामता चंद, इन दोनों का आया ओर. ओर निभाना यानी अंत तक अपना कर्तव्य पूरा करना. ओर शब्द हिंदी का अवयव शब्द है, जो मुख्यतः संयोजक है. यानी ओर शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़नेवाला शब्द है. जैसे छोड़े और गढ़ते चर रहे हैं. हमने उनको पुस्तक दे दी और घर का रास्ता दिखला दिया. विशेषण के रूप में ओर का मतलब है दूसरा, अन्य, भिन्न. यह पुस्तक किसी ओर को न देना. ओर से बने मुहावरों का प्रयोग बहुत ही रोचक होता है. जैसे ओर ओर यानी अन्यथा, विभिन्न प्रकार के. ओर क्या? सवाल है तुम वहां जाओगे? जवाब है-ओर क्या?

## शब्द चर्चा

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय

### ओर/ और

जरा उस मैदान की ओर देखिए, जहां गंधे और छोड़े एक साथ घास चर रहे हैं. उस स्रिता की ओर देखिए, जहां बाघ और बकरी एक साथ घास पाती पीते हैं. इन वाक्यों में कुछ अंतरों के बावजूद एक जैसे लगनेवाले दो शब्द सामने हैं- ओर तथा ओर. दोनों शब्दों की प्रकृति से पूरी तरह परिचित नहीं होने के कारण कुछ लोग और की जगह ओर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि दोनों शब्दों के बीच काफी अंतर है. और संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका मतलब है किनारा, किसी नियत स्थान के अतिरिक्त विस्तार जिसे दाहिना बायां, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम आदि शब्दों से निचयित करते हैं. तरफ, दिशा. पक्ष. जैसे यह उनकी ओर का आदर्मी है. हम आपकी ओर से बहुत कुछ कहेंगे. मजेदार बात यह है कि ओर संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अगर ओर कहलते कोई संख्यावाचक शब्द आता है, तब इसका व्यवहार पुल्लिंग की तरह होता है. जैसे घर के चारों ओर, उसके दोनों ओर. वैसे ओर संज्ञा पुल्लिंग रूप में भी व्यवहार में आता है, जिसका मतलब है अंत, सिरा, छोर, किनारा, आदि, आरंभ. कहते हैं कि उसकी बातों का न कोई ओर है न छोर. ओर आना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है नाश का समय आना. उदाहरण के लिए हंसता ठाकुर, खामता चंद, इन दोनों का आया ओर. ओर निभाना यानी अंत तक अपना कर्तव्य पूरा करना. ओर शब्द हिंदी का अवयव शब्द है, जो मुख्यतः संयोजक है. यानी ओर शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़नेवाला शब्द है. जैसे छोड़े और गढ़ते चर रहे हैं. हमने उनको पुस्तक दे दी और घर का रास्ता दिखला दिया. विशेषण के रूप में ओर का मतलब है दूसरा, अन्य, भिन्न. यह पुस्तक किसी ओर को न देना. ओर से बने मुहावरों का प्रयोग बहुत ही रोचक होता है. जैसे ओर ओर यानी अन्यथा, विभिन्न प्रकार के. ओर क्या? सवाल है तुम वहां जाओगे? जवाब है-ओर क्या?

# आम बजट 2024 की आर्थिक दिशा

जब हर व्यक्ति के पास सम्मानजनक रोजगार होगा, तो उसका जीवन स्तर क्रमिक रूप से उठेगा और समाज समृद्ध एवं खुशहाल बनेगा. ऐसे समाज में आमदनी बढ़ने के कारण कर उगाही भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, जिससे सरकारी जन-कल्याण एवं पुख्ता सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर संकेगी. यानी कुल सोच यह थी कि पूँजीवाद धन पैदा करेगा, जो धीरे-धीरे रिस कर निचले तबकों तक पहुंचेगा. इस तरह सभी खुशहाल होंगे.

## लो

कसबा चुनाव के दौरान ही ये बात जाहिर हो गई कि 'विकसित भारत' का नारा लोगों को उदासित या आकर्षित नहीं कर रहा है. इसके प्रति लोगों की उदासीनता का आलम यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने पहले चरण के मतदान के बाद अपने प्रचार अभियान में इस थीम को हाशिये पर डाल दिया. इसके विपरीत हिंदुत्व का डोज (खुराक) बढ़ाने का दांव उन्होंने चला. वह भी कितना कारगर रहा, यह चार जून को आए चुनाव नतीजों से जाहिर हो चुका है. यह निर्विवाद है कि लोकसभा के चुनाव का प्रमुख कथानक महंगाई, बेरोजगारी, अवसरहीनता आदि जैसे ठोस और रोजमर्रा की जिवंदी की जुड़े मुद्दों से तय हुआ. इसके बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 'विकसित भारत' अपना थीम बनाए रखा है तो यही कहा जाएगा कि हकीकत से आंख मिलाने का साहस या क्षमता उसमें नहीं है. पिछले महिने संसद के सभा सत्र में दिए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एलान किया था कि 2024-25 के बजट में सरकार 'विकसित भारत' की कार्यसूची पेश करेगी. 23 जुलाई को पेश बजट को मोदी सरकार ने 'विकसित भारत की तरफ यात्रा का रोडमैप' कहा है. इसमें पेज-पेज 'विकसित भारत का प्राथमिकताएं' बताई गई हैं. यानी जो जुमला चुनाव अभियान में लोगों को लुभा नहीं सका, जिस पर लोगों ने यकीन नहीं किया, उसे ही इस बजट का मुख्य विषयवस्तु बनाया गया है. इसलिए यह सवाल विचारणीय हो जाता है कि आखिर किसी अर्थनीति और विकास नीति का मकसद क्या होना चाहिए? उनकी सरलता का पैमाना क्या होना चाहिए? बीसवीं सदी के आरंभ में जब सोवियत क्रांति के साथ समाजवाद सपनों की रूमाानी दुनिया से उतर कर जमीनी हकीकत का रूप लेना लगा तो पहली बार तत्कालीन पूँजीवादी और अन्य व्यवस्थाओं के सामने भी अपना लक्ष्य तय करने और कुछ खपने जमाने की चुनौती पेश आई थी. क्या पूँजीवाद आधारित 'लोकतंत्र' खुद में सामाजिक एजेंडा जोड़ कर समाजवादी क्रांति का विकल्प पेश सकता है, यह बहस खड़ी हुई थी. उसी दौर में जॉन मेनार्ड कीन्स ने अर्थनीति संबंधी अपनी समग्र दुनिया के सामने रखी, जो धीरे-धीरे पूरे पूँजीवादी विश्व का स्वीकृत आर्थिक एजेंडा बन गई. कीन्स की आर्थिकी ने "क्रांतिकारी समाजवाद" के विकल्प के रूप में "शांतिमय



प्रगति आधारित लोकतांत्रिक पूँजीवाद' के लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के मार्ग की व्याख्या की थी. बताया गया कि इस अर्थनीति का पालन करते हुए संपूर्ण रोजगार हासिल किया जा सकता है. जब हर व्यक्ति के पास सम्मानजनक रोजगार होगा, तो उसका जीवन स्तर क्रमिक रूप से उठेगा और समाज समृद्ध एवं खुशहाल बनेगा. ऐसे समाज में आमदनी बढ़ने के कारण कर उगाही भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, जिससे सरकारी जन-कल्याण एवं पुख्ता सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर संकेगी. यानी कुल सोच यह थी कि पूँजीवाद धन पैदा करेगा, जो धीरे-धीरे रिस कर निचले तबकों तक पहुंचेगा. इस तरह सभी खुशहाल होंगे. इस आर्थिकी को कार्यरूप देने के लिए कीन्स ने अर्थव्यवस्था में सरकारों की सक्रिय भूमिका की वकालत की थी. सामाजिक लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करने की तरफ समाज को ले जाना सरकारों की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी मानी गई. फुल पैलायममेंट इन लक्ष्यों में सर्व-प्रमुख था. पूँजीपति और धनिक तबकों ने अपनी नव-उदारवादी मुहिम के तहत इसी सोच पर हमला बोला. 1980 का दशक आते-आते उनकी यह मुहिम कामयाबी की राह पर चल निकली.

## देश-काल



सत्येंद्र रंजन

1990 के दशक में इस सोच और इस पर आधारित आर्थिकी का लगभग सारी दुनिया में प्रसार हो गया. 1991 में यह आर्थिकी भारत पहुंची और आज उसका सबसे विदूष चहेरा हमारे सामने है. ताजा बजट ने यही दिखाना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इन विदूषता से भारत की इच्छाशक्ति और समझ का सिरे से अभाव है.

बेरोजगारी और महंगाई जैसे प्रश्नों पर वह नव-उदारवादी फॉर्मूलों पर पुनर्विचार करने तक को तैयार नहीं है. चूंकि हाल के आम चुनाव में इन दोनों समस्याओं के कारण उसे गंभीर झटके लगे, इसलिए वह इस दिशा में कुछ करते तो दिखना चाहती है, लेकिन सचमुच कुछ करना नहीं चाहती! महंगाई के सवाल पर तो उसने आम-समर्पण कर दिया है. इस बात का प्रमाण 22 जुलाई को संसद में पेश 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिला. इसमें खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई दर का जिक्र किया गया और इसका कारण आपूर्ति संबंधी दिक्कतों को बताया गया. रिपोर्ट में कहा गया है: 'अक्सर खाद्य पदार्थों की महंगाई का कारण मांग से संबंधित नहीं, बल्कि आपूर्ति से संबंधित है.' तो इस रिपोर्ट के जरिए सरकार ने दलील दी है कि व्याज दरें बढ़ा कर महंगाई पर काबू पाने का तरीका मौजूदा खाद्य महंगाई के संदर्भ में कारगर नहीं होगा. इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से सिफारिश की गई है कि वह खाद्य पदार्थों के अलावा बाकी मुद्रास्फूर्ति दर पर गौर करें, जो अब नियंत्रण में है. यानी वह व्याज दरों में कटौती शुरू कर दे. मतलब, सरकार मानती है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई इसलिए है कि किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. क्या यह सच है? क्या इस बात को हकीकत किया जा सकता है? दरअसल, आज की मोनोपॉली नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दौर में महंगाई सिर्फ मांग और आपूर्ति के अपसी संघर्ष से तय नहीं हो रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसाबेला बेवर जैसी अर्थशास्त्री और भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने अनुसंधानों से यह साबित किया है कि महंगाई का एक बड़ा कारण मोनोपॉली है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे धिक्का और महंगाई के लिए (ये लेखक के निजी विचार हैं)

# कृषि में सुधार की संभावना

### आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की विकास कहानी की एक सुखद तस्वीर पेश करता है और अल्पकालिक संभावनाओं को अच्छा मानता है, लेकिन चिंता के कई क्षेत्रों को चिह्नित करने में विफल नहीं होता है. बेहतर दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए यह सुवदशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है. इसने कृषि में व्यापक सुधार की तत्काल जरूरतों को रेखांकित किया- भारत के विकास पथ में अपनी केंद्रीयता के बावजूद, कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसने क्षेत्र के सामने कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए कहा, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फूर्ति का प्रबंधन करते हुए विकास को बनाये रखने की आवश्यकता, फसलों के मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार और भूमि विखंडन को संबोधित करना शामिल है. इसमें कहा गया है कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक नाजूक संतुलन बनाना चाहिए. इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है. हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह चेतावनी देता है कि आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कुत्रिम बुद्धिमता को जड़े जम रही हैं और इसलिए सार्वजनिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, यह सरकार पर नहीं, बल्कि नियोजकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रौद्योगिकी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं. इसमें कहा गया है कि कई विनियामक प्रतिबंध, जैसे कि भूमि उपयोग, भवन संहिता, महिलाओं के रोजगार के लिए खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करना, रोजगार सृजन को रोकते हैं. सर्वेक्षण ने रुपये की अस्थिरता को नोट किया, लेकिन कहा कि यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है, जो संतुलन के अलावा एक बड़ा नहीं है. वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर ने लगभग हर प्रमुख समकक्ष के मुकाबले बहुत हासिल की. रुपया भी मूल्यह्रास के दबाव में आया. इसके अलावा, दरतावज में जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 24 में इसने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की. यह विश्व अर्थव्यवस्था पर चीन के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख करता है और कहता है कि दुनिया चीन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर

### सर्वेक्षण कहता है कि यह 1980 और 2015 के बीच चीन के आर्थिक उछाल से अलग होगा और यह एक आसान रास्ता नहीं होगा. यह कारण गिनता है कि क्यों? यह कहता है कि शीत युद्ध के अंत में भू-राजनीति काफी हद तक शांत थी और पश्चिमी शक्तियों ने चीन का स्वागत किया और यहां तक कि इसके उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया. वैश्वीकरण अपने लंबे विस्तार के शिखर पर था और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक नेतावनी पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं, जितनी कि वे अब हैं. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की ओर इशारा करता है, जो सभी कौशल स्ट्रो-निम्न, अर्थ और उच्च-के श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी परत डालता है. ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर के लिए अवरोध और बाधाएं पैदा करेंगे. इन पर काबू पाने के लिए अर्थ और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक शानदार गठबंधन की आवश्यकता है. देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यह कहता है कि हम कल्याण के लिए एक सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो सशक्तिकरण, संतुष्टि दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निजीक्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है. (ये लेखक के निजी विचार हैं)

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की विकास कहानी की एक सुखद तस्वीर पेश करता है और अल्पकालिक संभावनाओं को अच्छा मानता है, लेकिन चिंता के कई क्षेत्रों को चिह्नित करने में विफल नहीं होता है. बेहतर दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए यह सुवदशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है. इसने कृषि में व्यापक सुधार की तत्काल जरूरतों को रेखांकित किया- भारत के विकास पथ में अपनी केंद्रीयता के बावजूद, कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसने क्षेत्र के सामने कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए कहा, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फूर्ति का प्रबंधन करते हुए विकास को बनाये रखने की आवश्यकता, फसलों के मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार और भूमि विखंडन को संबोधित करना शामिल है. इसमें कहा गया है कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक नाजूक संतुलन बनाना चाहिए. इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है. हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह चेतावनी देता है कि आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कुत्रिम बुद्धिमता को जड़े जम रही हैं और इसलिए सार्वजनिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, यह सरकार पर नहीं, बल्कि नियोजकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रौद्योगिकी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं. इसमें कहा गया है कि कई विनियामक प्रतिबंध, जैसे कि भूमि उपयोग, भवन संहिता, महिलाओं के रोजगार के लिए खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करना, रोजगार सृजन को रोकते हैं. सर्वेक्षण ने रुपये की अस्थिरता को नोट किया, लेकिन कहा कि यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है, जो संतुलन के अलावा एक बड़ा नहीं है. वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर ने लगभग हर प्रमुख समकक्ष के मुकाबले बहुत हासिल की. रुपया भी मूल्यह्रास के दबाव में आया. इसके अलावा, दरतावज में जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 24 में इसने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की. यह विश्व अर्थव्यवस्था पर चीन के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख करता है और कहता है कि दुनिया चीन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर

## कृषि

### डॉ. ज्ञान पाठक

कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसने क्षेत्र के सामने कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए कहा, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फूर्ति का प्रबंधन करते हुए विकास को बनाये रखने की आवश्यकता, फसलों के मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार और भूमि विखंडन को संबोधित करना शामिल है. इसमें कहा गया है कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक नाजूक संतुलन बनाना चाहिए. इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है. हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह चेतावनी देता है कि आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कुत्रिम बुद्धिमता को जड़े जम रही हैं और इसलिए सार्वजनिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, यह सरकार पर नहीं, बल्कि नियोजकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रौद्योगिकी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं. इसमें कहा गया है कि कई विनियामक प्रतिबंध, जैसे कि भूमि उपयोग, भवन संहिता, महिलाओं के रोजगार के लिए खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करना, रोजगार सृजन को रोकते हैं. सर्वेक्षण ने रुपये की अस्थिरता को नोट किया, लेकिन कहा कि यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है, जो संतुलन के अलावा एक बड़ा नहीं है. वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर ने लगभग हर प्रमुख समकक्ष के मुकाबले बहुत हासिल की. रुपया भी मूल्यह्रास के दबाव में आया. इसके अलावा, दरतावज में जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 24 में इसने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की. यह विश्व अर्थव्यवस्था पर चीन के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख करता है और कहता है कि दुनिया चीन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर

सर्वेक्षण कहता है कि यह 1980 और 2015 के बीच चीन के आर्थिक उछाल से अलग होगा और यह एक आसान रास्ता नहीं होगा. यह कारण गिनता है कि क्यों? यह कहता है कि शीत युद्ध के अंत में भू-राजनीति काफी हद तक शांत थी और पश्चिमी शक्तियों ने चीन का स्वागत किया और यहां तक कि इसके उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया. वैश्वीकरण अपने लंबे विस्तार के शिखर पर था और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक नेतावनी पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं, जितनी कि वे अब हैं. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की ओर इशारा करता है, जो सभी कौशल स्ट्रो-निम्न, अर्थ और उच्च-के श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी परत डालता है. ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर के लिए अवरोध और बाधाएं पैदा करेंगे. इन पर काबू पाने के लिए अर्थ और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक शानदार गठबंधन की आवश्यकता है. देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यह कहता है कि हम कल्याण के लिए एक सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो सशक्तिकरण, संतुष्टि दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निजीक्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है. (ये लेखक के निजी विचार हैं)

सर्वेक्षण कहता है कि यह 1980 और 2015 के बीच चीन के आर्थिक उछाल से अलग होगा और यह एक आसान रास्ता नहीं होगा. यह कारण गिनता है कि क्यों? यह कहता है कि शीत युद्ध के अंत में भू-राजनीति काफी हद तक शांत थी और पश्चिमी शक्तियों ने चीन का स्वागत किया और यहां तक कि इसके उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया. वैश्वीकरण अपने लंबे विस्तार के शिखर पर था और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक नेतावनी पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं, जितनी कि वे अब हैं. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की ओर इशारा करता है, जो सभी कौशल स्ट्रो-निम्न, अर्थ और उच्च-के श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी परत डालता है. ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर के लिए अवरोध और बाधाएं पैदा करेंगे. इन पर काबू पाने के लिए अर्थ और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक शानदार गठबंधन की आवश्यकता है. देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यह कहता है कि हम कल्याण के लिए एक सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो सशक्तिकरण, संतुष्टि दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निजीक्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है. (ये लेखक के निजी विचार हैं)

## मीडिया में अन्त्यर

# पूँजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाने वाला बजट

केंद्रीय बजट में एक अच्छी बात रही पूँजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाना. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने कहा कि चुनिंदा वित्तीय परिस्थितियों पर अल्पावधि का पूँजीगत लाभ कर 20 फीसदी की दर से लगाया जाएगा जबकि पहले यह 15 फीसदी की दर से लगाया जाता था. अन्य सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिस्थितियों पर उसी दर से कर लगेगा. इसका अर्थ



रमता जोगी : इंग्लैंड

## ये महल सुनाते दास्तां क्वीन विक्टोरिया की



इंग्लैंड दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहाँ आज भी राजा-रानी का राज है। उनके कई राजमहल पर्यटकों के लिए पूरे या आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। इन सब के लिए प्रवेश शुल्क है जिसे पहले से ही लेना होता है। बकिंगहम पैलेस इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। इसमें रहने वाली प्रथम राजसी व्यक्ति क्वीन विक्टोरिया थीं जो 1837 में अपने राज्याभिषेक के उपरांत यहां रहने लगीं। 1861 में अपने वैधव्य के बाद वे इसे छोड़ कर विंडसर पैलेस में चली गईं जो लंदन के मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर है। 1901 में नए राजा एडवर्ड सप्तम ने फिर इसे अपना निवास बनाया। आज भी राजपरिवार यहां रहता है।



नूपुर अशोक

इसके सामने होने वाले चेज ऑफ गाइड्स को देखने हर दिन भारी भीड़ जमा होती है। केंसिंग्टन पैलेस शहर के बीचोबीच है। अब यहां कोई नहीं रहता लेकिन कुछ समय पहले तक यह प्रिंसेस डायना का निवास स्थल था। क्वीन विक्टोरिया का जन्म भी इसी महल में हुआ था। उनके बचपन के खिलौने, उनकी गुड़ियों का कमरा, पढ़ाई-लिखाई का कमरा यहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उनके पहले और बाद के राज परिवार के कपड़े, उनके चित्र इत्यादि भी यहां प्रदर्शित हैं। महल के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध ऑडियो गाइड हर कमरे की कहानी और उससे संबंधित बातें बताता चलता है।

### प्रिंसेस डायना का यह निवास स्थल

इसके सामने होने वाले चेज ऑफ गाइड्स को देखने हर दिन भारी भीड़ जमा होती है। केंसिंग्टन पैलेस शहर के बीचोबीच है। अब यहां कोई नहीं रहता लेकिन कुछ समय पहले तक यह प्रिंसेस डायना का निवास स्थल था। क्वीन विक्टोरिया का जन्म भी इसी महल में हुआ था। उनके बचपन के खिलौने, उनकी गुड़ियों का कमरा, पढ़ाई-लिखाई का कमरा यहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उनके पहले और बाद के राज परिवार के कपड़े, उनके चित्र इत्यादि भी यहां प्रदर्शित हैं। महल के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध ऑडियो गाइड हर कमरे की कहानी और उससे संबंधित बातें बताता चलता है।

### स्मृति को समर्पित

महल के बाहर के उद्यान भी देखने योग्य हैं। इनमें से एक डायना की स्मृति को समर्पित है। विंडसर कासल आज के राजा चार्ल्स तृतीय का निवास स्थान है। उनका राज्याभिषेक इसी महल के प्रांगण में हुआ था। इस महल का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला हुआ है जहां राजपरिवार द्वारा एकत्रित कलाकृतियां और अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शित हैं। यहां हमारा कोहिनूर टावर ऑफ लंदन टेम्स नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक बहुत पुराना

### कभी-कभी अपनों से हमारी दूरी बढ़ जाती है। हम मन ही मन उस व्यक्ति को कोसते हैं, अंदर की भड़ास निकालने के लिए फेसबुक-व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, दो-चार लोगों से अपना दर्द शेर भी करते हैं। लेकिन इससे दूरियां कम नहीं होतीं। क्या हर बार सामने वाले की गलती होती है? इस बारे में सोचने की जरूरत है, आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है, दूरी बढ़ने के पीछे किसी ने किसी पक्ष की गलती तो होती है। कहीं ये गलतियां हम तो नहीं कर रहे, आइए इस पर गौर करें -

जवाहराती से अधिक कोहिनूर को देखने की थी। जिस कक्ष में इसे रखा गया है उसकी दीवारों पर इससे संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित थी। उस जानकारी के अनुसार यह एक ऐसा नगना है जो हमेशा हस्तांतरित होता रहा। कभी यह मुगलों के पास था, कभी नादिर शाह के पास, कभी पंजाब के महाराजा के पास, ग्याह वकीय महाराजा दलीप सिंह ने महाराजा विक्टोरिया को भेंट कर दिया था। अब यह वर्तमान राजा चार्ल्स की संपत्ति है। इस पर भारत अपना दावा तो करता ही रहा है, समय-समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी अपना दावा करते रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि यह स्वेच्छा से दी गई भेंट है इस कारण इसे लौटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

### क्वेंहेम पैलेस और हैपटन कोर्ट

इन सबके अलावा ब्लेहेम पैलेस और हैपटन कोर्ट भी दो दर्शनीय महल हैं। ब्लेहेम पैलेस विंस्टन चर्चिल के परिवार को 18वीं सदी के प्रारम्भ में भेंटस्वरूप दिया गया था। सैकड़ों एकड़ की जागीर के बीच स्थित इस शानदार महल में उस पूरे खानदान के चित्र और उनसे संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित हैं। सोलहवीं सदी में बने हैपटन कोर्ट में रहने वाले अंतिम राजा जॉर्ज द्वितीय थे। उनके बाद कोई राजा यहां नहीं रहा लेकिन कई फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। आज भी हर दिन सैकड़ों लोग इसे देखने आते हैं और यहां उपलब्ध ऑडियो गाइड पर इसकी कहानी सुनते हुए पूरे किले और इसके उद्यानों का भ्रमण करते हैं। इतिहास की ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारे वर्तमान की जड़ें कहां से कहाँ तक पसरी हुई हैं।

## होम डेकोर बोनचाइना प्लेट या वाल आर्ट

पुरानी क्रॉकरी जैसे बोन चाइना प्लेट्स उपयोग के बाद घर अब पैदा कर रही हो या फिर टूटन-फूटने के बाद अब बची कुछ प्लेट्स मिस मैच हो रही हों तो उस पर अपनी रचनात्मकता का रंग चढ़ाएं, अपनी पुरानी प्लेटों को अलग-अलग केंडी रंगों में पेंट करें और अपनी दीवारों का साज सज्जा का एक ऐसा अंदाज दें जिसे कोई किसी दुकान से ला कर नहीं मुकाबला कर सके।



दादी-नानी के जमाने की सुजनी-लेदरा कला एक बार फिर पैचवर्क के नाम से चलन में है और इस बार पर्यावरण हित का झंडा उठाए है। पुराने कपड़ों जैसे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, फ्रॉक, आपके खुद के कपड़े आदि के छोटे-छोटे टुकड़ों को इच्छानुसार आकार में काट कर कियी पुरानी बेडशीट पर पैच करके पैचवर्क ब्लैकबोर्ड तैयार किया जा सकता है जो रंग-बिरंगा तो होगा ही, कई स्मृतियों को सजाने वाला भी।

## मोटिवेशन

# संबंधों का यह जोड़-घटाव



डॉ. कुमार संजय  
शिखाविद

**1. नेटवर्क मार्केटिंग :** कुछ लोग नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन करते हैं। फिर वे सभी जान-पहचान वालों के पीछे पड़ जाते हैं। वे अपने करीबी लोगों को अपने नेटवर्किंग बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए दिन-रात फोन घुमाते हैं और अनावश्यक दबाव डालते हैं। स्वाभाविक है, लोग उनको अवांछित करने लगते हैं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे?

**2. इन्फ्लुएंसर तथा फिनांशियल सेक्टर में होते हैं, वे भी अपनी सीमा क्रॉस करने लगते हैं, खासकर जब उन्हें टारगेट पूरा करना रहता है।** हर किसी को पॉलिसी समझाने लगते हैं, और उन्हें पॉलिसी पकड़ाने पर तुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही फिनांशियल इन्वेस्टर करते हैं। वे जबरदस्ती सलाह देने पर उतर आते हैं कि सामने वाले को पैसा कहाँ-कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि सामने वाला उसमें बिल्कुल इंटरस्टेड नहीं होता। उनका यह अप्राच संबंधों में खटाव ले आता है।

**3. प्रोडक्ट बेचना :** कई लोग डायरेक्ट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं जहाँ प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता है। ये हर जगह कंपनी का विज्ञापन करते नजर आते हैं। दोस्त, या, रिश्तेदार को कंपनी का प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए फोर्स

**4. इन्फ्लुएंसर तथा फिनांशियल सेक्टर में होते हैं, वे भी अपनी सीमा क्रॉस करने लगते हैं, खासकर जब उन्हें टारगेट पूरा करना रहता है।** हर किसी को पॉलिसी समझाने लगते हैं, और उन्हें पॉलिसी पकड़ाने पर तुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही फिनांशियल इन्वेस्टर करते हैं। वे जबरदस्ती सलाह देने पर उतर आते हैं कि सामने वाले को पैसा कहाँ-कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि सामने वाला उसमें बिल्कुल इंटरस्टेड नहीं होता। उनका यह अप्राच संबंधों में खटाव ले आता है।

**5. कड़वी जुबान :** कुछ लोग दिल के बुरे नहीं होते लेकिन जुबान कड़वी रखते हैं। बहुत बार दिल को चुभने वाली बात कह डालते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई एक दूरी

**6. प्रोफेशनल सलाह :** मान लीजिए हमारा कोई करीबी डॉक्टर है, पार्टी, प्रोग्राम, गेट टूगेदर में उससे मिलने पर हम उसे अपनी समस्या बताने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह हमें सलाह दे, दवाइयां बताए, हम यह भूल जाते हैं कि वह भी पार्टी में गेस्ट बन कर आया है, इंजॉय करने आया है, पार्टी, पिकनिक सोशल गैदरिंग में प्रोफेशनल हेल्प न लें, यह शिष्टाचार के खिलाफ है और यह दूरी बढ़ाता है।

**7. उधार :** अगर संबंध बनाए रखना है तो न किसी को उधार दें, न किसी से उधार लें। उधार अच्छे से अच्छे संबंध में दार ले आता है, भले बुरा लगे लेकिन विनम्रता से उधार मांगने वाले को मना कर दें, और खुद गांठ बांध लें कि आप किसी से किसी हाल में उधार नहीं मांगेंगे।

**8. अनावश्यक सलाह :** खुद हर्बल टी पीते हैं, तो पूरी दुनिया को हर्बल टी पिलाने पर उतारू हो जाते हैं। खुद कुछ टॉनिक लेते हैं, तो हर शख्स को टॉनिक खिलाने लगते हैं। कुछ बड़े हर बच्चे को पढ़ाई, करियर की अनावश्यक खुराक पिलाने पर आमादा हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों से कौन सटना चाहेगा भला !

**9. शो ऑफ :** शो ऑफ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है खासकर मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास के लिए आईफोन, लज्जरी गाड़ी, स्पॉटर्स बाइक, फ्लैट बड़ी उपलब्धियां हैं। वे हर किसी को पकड़ कर अपनी 'लेटेस्ट बाई' दिखाए लगते हैं, उसका मूल्य बताते हैं, और अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने लगते हैं तो लोग भागने का रास्ता ढूँढ़ने लगते हैं। भाई मेरे, आप प्रोडक्ट खरीदें, शानदार जिंदगी जिएं लेकिन दिखावे से बचें।

**10. बेचारीगी :** कुछ लोग हर किसी को पकड़ कर अपनी समस्या बताने लगते हैं, अपनी बेचारी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। हर व्यक्ति अपनी समस्या से जुड़ा रहा है। उसपर अपनी समस्या का बोझ क्यों थोपना, बेहतर होगा, हम अपनी समस्या अपने तक रखें।

## उफ! कपड़ों की ये स्मेल

बारिश के मौसम में कपड़ों से आने वाली गुमसाइन सी गंध कई बार परेशान कर देती है। ऐसा धूप की किल्लत और हवा में नमी के कारण होता है। इससे बचने के लिए कुछ टिप्स...

- कपड़े धोने की टोकरी या वॉशिंग मशीन में ढेर लगाकर नहीं रखें, तभी वॉशिंग मशीन में रखें जब धोना हो।
- कपड़े धोने के बाद नींबू का रस मिला पानी में कपड़े डालें और फिर सादे पानी से धो लें। इसके लिए नींबू की जगह सिरका का उपयोग भी कर सकते हैं।
- एक बाट्टी पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा डालें और कपड़ों को थोड़ी देर के लिए उसमें भिगो दें। इसके बाद उन्हें सादा पानी से धो लें।
- अपने वार्डरोब में चॉक या सिलिकॉन पाउडर रखें, तेजपात, दालचीनी, लौंग आदि को सूती कपड़े की पोटीली बना कर रखना भी लाभप्रद होगा।
- बाहर घुप न हो तो कपड़े मशीन में सुखाने की अपेक्षा अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर सुखाएं, कमरे में पंखा चला कर सूखाना भी बेहतर विकल्प है।
- कपड़ों को सूखी जगह पर रखें।

## पुरुषों के ग्रूमिंग टिप्स

आज प्रजेंटेबल रहना प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनललहर जगह की जरूरत है। खास बात यह कि प्रजेंटेबल या ग्रूमिंग टिप्स अब केवल महिलाओं की बात नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है। आइए, आज जानें पुरुषों के कुछ ग्रूमिंग और स्किन केयर टिप्स के बारे में।

- पहले शेविंग करें फिर नहाएं ज्यदातर पुरुष प्रतिदिन शेविंग करते हैं। लेकिन इनमें प्रायः सभी पहले शेविंग करते हैं और फिर नहाते हैं। यह सही नहीं है। इससे स्किन कटने, रैशस होने और एक्ने होने के चांसस होते हैं। शेविंग नहाने के बाद करें। इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और गीली त्वचा पर शेविंग अच्छे से होती है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स सॉफ्ट हो जाते हैं।
- कंडीशनर का इस्तेमाल यहां अंडर आर्म और प्राइवेट पार्ट की शेविंग के लिए अच्छे कंडीशनर का इस्तेमाल शेविंग क्रीम की तरह किया जा सकते हैं। ये बेहतर परिणाम देते हैं।

## हैंडसम, प्रजेंटेबल लुक

आज प्रजेंटेबल रहना प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनललहर जगह की जरूरत है। खास बात यह कि प्रजेंटेबल या ग्रूमिंग टिप्स अब केवल महिलाओं की बात नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है। आइए, आज जानें पुरुषों के कुछ ग्रूमिंग और स्किन केयर टिप्स के बारे में।

- स्क्रब है जरूरी पुरुषों को भी अपने किट में एक अच्छा स्क्रबर जरूर रखना चाहिए। उनकी रफ टफ स्कीन के लिए स्पेशल स्क्रबर मार्केट में उपलब्ध हैं। इनका हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल जरूर करें। इससे न केवल एक्सफोलिएशन होगा, बल्कि ब्लैकहेड्स रिमूव होंगे, मृत त्वचा हटेंगी। स्क्रबिंग के लिए रात का समय ठीक रहेगा।
- पफी फेस करें नॉर्मल मेकअप से पहले स्किन पर आइस लगाना या फिर आइस वॉटर में मुह डाल कर थोड़ी देर रखना... ये टिप्स आपने भी महिलाओं को आजमाते देखा होगा। हैंगओवर, पफी फेस के लिए यह टिप्स आप भी आजमाएं। इसके लिए एक बाउल में आइस और उसमें थोड़ा पानी डालकर फेस डिप करें, लुक का फ्रेंसनेश साफ नजर आएगा।
- कॉफी फिल्टर्स काम के स्किन ऑयली वालों के लिए यह टिप्स बेहद कारगर है। इसके लिए कॉफी फिल्टर शीट्स को कॉफी में डिप करें ऑयली स्किन एरिया पर अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी त्वचा साफ और मैट दिखने लगेगी।

## मानसून पेट केअर गाइड

# बारिश में हो सकता है शेरू को फंगल इंफेक्शन

**बरसात का मौसम आपके दुलारे डॉगी के लिए थोड़ा संवेदनशील है। इस मौसम में उनके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की किसी एलर्जी के प्रति हाइपरसेंसिटिविटी या ओवर रिएक्टिविटी की स्थिति रहती है। खासकर डॉग्स की कुछ नस्लों में एलर्जी की आशंका अधिक होती है। आइए जाने कि बरसात के मौसम में अपने पालतू डॉग्स की कैसे करें देखभाल-**

एलर्जी से बचाएं इस मौसम में डॉग्स के कुछ नस्ल में एलर्जी की आशंका होती है। डॉग्स में एलर्जी के मुख्य लक्षण नाक बहना, सांस फूलना, गले में घरघराहट, आंखें लाल होना, खुजली होना और बाल झड़ना इत्यादि हो सकते हैं। एलर्जी के लक्षण दिखाई देते ही सबसे पहले वेटरनरी डॉक्टर से मिलें। डॉग के लक्षण और जांच के आधार पर यह पता चलता है कि किस प्रकार की एलर्जी है और क्यों हुई है। उपचार के लिए डॉग को जरूरत के अनुसार एंटी एलर्जी दवाइयां और स्टैरोइड्स दी जाती हैं।

प्रतिदिन नहलाएं इस मौसम में अपने डॉगी को नियम से नहलाएं ताकि उनके शरीर की गंदगी साफ हो जाए, नियमित रूप से उनके पंजों की साफ करें। फंगल इंफेक्शन को रोकने और टंड से बचाने के लिए नहाने के बाद उन्हें शरीर के हर एक हिस्से को अच्छी तरह सुखाएं, फर पर नियमित रूप से ब्रश करें।

भींगने से बचाएं बरसात में अव्वल तो अपने डॉगी को भींगने

से बचाएं, गर भींग गया है तो उसे तुरंत सुखाएं। आप उसे तौलिए से अच्छे से पोछकर सुखा सकते हैं।

घर में ही रखें बरसात के मौसम में अपने जानवरों को अपने घर में ही साफ-सूखी जगह पर रखें। घर के अंदर गर्माहट बनी रहती है, बाहर ठंड से बीमार पड़ सकता है। कीड़े-कौट काटने की आशंका भी रहती है।

पैरासाइट प्रोटेक्शन मानसून का सीजन पिस्सू, कौटों और मच्छरों के लिए प्रजनन का मौसम भी है, जो आपके डॉग के लिए परेशानी भरा हो सकता है। इन परजीवियों से बचाव के लिए अपने पशु चिकित्सक से परामर्श लें। संक्रमण को कम करने के लिए नियमित रूप से विस्तर, इनडोर जगहों की साफ-सफाई करें।

**डाइट और लिक्विड्स** मानसून के दौरान, पालतू जानवर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, जिससे उनका वजन बढ़ सकता है, तो मोटापे से बचाने के लिए उनकी डाइट में भी मौसम के अनुसार बदलाव करें। साथ ही वो किलोना पानी पी रहे हैं, इस पर भी नजर रखें। क्योंकि कई बार प्यास लगने पर वो जगह-जगह भरा हुआ पानी पी लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए उन्हें हमेशा ताजा, फिल्टर किया हुआ पानी पीने के लिए दें।

**फिजिकल एक्सरसाइज** चूँकि इस मौसम में डॉग की आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, इसलिए अपने पालतू को फिट रखने के लिए घर में ही उन्हें खेलने का मौका दें। इंटरैक्टिव टॉयज और पजल गेम से वो एक्टिव और हेल्दी रहते हैं।

**नमी से दूर रखें** डॉगी में इंफेक्शन होने का खतरा भी रहता है। इसलिए उन्हें नमी वाली जगहों से दूर रखें।







राशिफल

आचार्य प्रणव मिश्रा

**मेघ**  
अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अपनों पर खर्च अधिक होगा, पर रोजगार की समस्या का समाधान भी संभव है। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। कर्मकांड दूर होगी। स्वजनों से भेंट होगी। नवगण मंत्र का जाप करें।

**वृषभ**  
किसी नए कार्य से आग्रह होगी। साथ ही व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रुभाव रहेगा। लाभ होगा। पिछले कार्यों को टालना चाहिए, क्योंकि उसमें असफलता का योग है। अनावश्यक विवाद होगा। व्यावसायिक योजनाएँ क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी।

**मिथुन**  
पिता का पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार के विस्तार हेतु किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। परिवार को चिंता रहने।

**कनक**  
भाग्य का साथ मिलेगा। सरकार या कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। कार्यसिद्धि होगी। आय-व्यय में संतुलन रहेगा। क्रोध पर संयम आवश्यक है। व्यापार में नए अनुभव लाभकारी रहेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी। नई योजना से लाभ होगा।

**सिंह**  
पूर्व किये कार्य का लाभ मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। जल्दबाजी व भागदौड़ से काम करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ। अच्छे मित्र से भेंट होगी। पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज-परिवार में आदर मिलेगा। गुड़ और जल का दान करें।

**कन्या**  
पाठन से विवाद न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। दायित्व जीवन सुखद रहेगा। पुत्री निवेश बढ़ेगा। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक योग्य शुभ है। यात्रा से व्यापारिक लाभ हो सकता है। सुसंगति से लाभ होगा। माता दुर्गा की सेवा करें।

**तुला**  
कुसंगति से बचें। दूसरों पर भरोसा न करें। धैर्य रखें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। रुका पैसा मिलेगा। शत्रु आपको छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। अंत-सावधान रहें। व्यापार में सफलता मिलेगी। जल और फल का दान करें।

**वृश्चिक**  
किसी से विवाद हो सकता है। किसी नया कार्य से अप्रत्याशित लाभ होगा पर जोखिम बिलकुल न लें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। व्यापार व नौकरी में हितवादीकों की पूर्ण कृपा रहेगी। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे।

**धनु**  
व्यवसाय ठीक चलेगा। कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न बाधाओं से मन अशांत रहेगा। विवादों से दूर रहना चाहिए। आर्थिक तंगी रहेगी। पिछले कार्यों को टालें। पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा। व्यापार में हानि हो सकती है।

**मकर**  
दिन खुशामना होगा। छोटे यात्रा सफल रहेगी। धनलाभ होगा। ससन्तता बनी रहेगी। वाहन सुख मिलेगा। संपत्ति के लेन-देन में सावधानी बरतें। पाटन व सतबवा की विभिन्न पंचायत सचिवों संग बैठक कर उनके क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम प्रगति वाली पंचायतों में अड्डा आवास योजना की समीक्षा की। इस दौरान डीडीसी श्री अहमद सभी पंचायत सचिवों से अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारणों से अवगत हुए, बताया गया कि कई लाभुक प्रथम किस्त लेने के बाद कार्य प्रारंभ नहीं किये हैं। इस पर डीडीसी ने ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस करने की बात कही। वहीं कुछ पंचायत सचिव द्वारा जियो टैग नहीं किया गया है, जिस कारण दूसरी किस्त का भुगतान की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसके अलावे प्रगति नहीं होने से संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर उप विभास आयुक्त द्वारा गहनता से समीक्षा किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी 33 पंचायत सचिवों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिये। कहा कि अगले एक सप्ताह में प्रगति नहीं होती है तो संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**कुंभ**  
क्रोध में बुद्धि हानि इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वगैरों से लाभ होगा। शिव मंदिर में श्राद्ध का दान करें।

**मीन**  
सूझ बुझ कर किया गया कार्य लाभ देगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। ध्यान रहेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पराक्रम बढ़ेगा। जीवनसाथी से आर्थिक मतभेद हो सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप स्थिति बनेगी। शिव मंदिर में श्राद्ध का दान करें।

33 पंचायत सचिवों का वेतन रोका

मेदिनीनगर। पलामू जिले के उप विभास आयुक्त शम्भू अहमद ने गुरुवार को अड्डा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विश्रामपुर, चैनपुर, हुसैनाबाद, नवाबाजार, लेस्लीगंज, पांडु, पडवा, पांकी, पाटन व सतबवा की विभिन्न पंचायत सचिवों संग बैठक कर उनके क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम प्रगति वाली पंचायतों में अड्डा आवास योजना की समीक्षा की। इस दौरान डीडीसी श्री अहमद सभी पंचायत सचिवों से अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारणों से अवगत हुए, बताया गया कि कई लाभुक प्रथम किस्त लेने के बाद कार्य प्रारंभ नहीं किये हैं। इस पर डीडीसी ने ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस करने की बात कही। वहीं कुछ पंचायत सचिव द्वारा जियो टैग नहीं किया गया है, जिस कारण दूसरी किस्त का भुगतान की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसके अलावे प्रगति नहीं होने से संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर उप विभास आयुक्त द्वारा गहनता से समीक्षा किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी 33 पंचायत सचिवों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिये। कहा कि अगले एक सप्ताह में प्रगति नहीं होती है तो संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

153 युवक-युवतियों को मिला रोजगार

लोहरदगा। सदर प्रखंड पर स्थित नगर भवन परिसर में लोहरदगा जिला के बेरोजगार युवक-युवतियों को सुगमता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, सरकार के तत्वावधान में जिला नियोजनालय, द्वारा एक दिवसीय दसोपत डेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इधर, मेला का उद्घाटन उप विभास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस रोजगार मेला के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र के नियोजकों के रिक्तिव्यों के लिए कुल 362 युवक-युवतियां शामिल हुए जिनमें से 153 युवक-युवतियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। मेला के लिए 42 सौ 60 रिक्तिव्यों नियोजकों की ओर से प्रस्तावित थीं। मौके पर उप विभास आयुक्त ने मेला में आये नियोजक कंपनियों को यहां के युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।

महोत्सव विधायक ने किया उद्घाटन, कहा- हमें अपनी विरासत को संजोकर रखना है

दो दिवसीय जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ

संवाददाता। बरवाडीह (लातेहार)

गुरुवार को पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (कोलकाता), संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) व रंगयात्रा लातेहार, झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय पलामू जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव की शुभारंभ रेलवे स्पोर्ट्स क्लब में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि मंत्रालय विधायक रामचंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि बरवाडीह पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शंकर, बीस सूत्री अध्यक्ष नसीम अंसारी एवं विधायक प्रतिनिधि प्रेम कुमार सिंह (पिट्ट) द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ



किया। आयोजन कमिटी द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन चंद्रदेव सिंह (संविन) भारतीय लोक कल्याण संस्थान (रांची) झारखंड जलछाजन योजना, बरवाडीह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकगीत एवं लोकनृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोक संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षण

सियासी पिच पर उतर सकते हैं सौरभ तिवारी

गृह मंत्री से मिले, भाजपा में शामिल होने के कयास

प्रमुख संवाददाता। रांची



क्रिकेटर सौरभ तिवारी सियासी पिच पर चौका-छक्का मारने को बेताब हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौरभ तिवारी की मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। गुरुवार को क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को पुस्तक भी भेंट की। कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है कि झारखंड में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले भाजपा के टॉप लीडर से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा हो रही है कि सौरभ तिवारी जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सौरभ तिवारी कई अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। आईपीएल में वे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी हिस्सा रह चुके हैं। झारखंड में सौरभ तिवारी का संबंध जमशेदपुर से है।

झारखंड विस का मॉनसून सत्र आज से, सुरक्षा चाक-चौबंद

छह डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर व 1000 जवान रहेंगे तैनात

संवाददाता। रांची

झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर छह डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर और 1000 जवानों की तैनाती की गयी है। एएसपी ने सत्र को लेकर सुरक्षाकर्मियों को ब्रीफिंग भी की है। सत्र के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो, सभी कर्मियों को इस पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में गश्त करने का निर्देश है।



आजसू ने पलायन रोकने पर विशेष चर्चा की मांग रखी

रांची। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर 17वें मासून सत्र में युवाओं के विकास कल्याण व रोजगार एवं पलायन रोकने पर विशेष चर्चा की मांग की है। उन्होंने मानसून सत्र में इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से समय निर्धारित करने की भी मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के अभाव में युवाओं के बीच निराशाजनक स्थिति है। राज्य में रोजगार न मिलने की वजह से राज्य के बाहर देश के अन्य राज्यों एवं विदेश में युवाओं एवं श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है, जिस पर राज्यहित में रोजगार उपलब्ध किये गये हैं। विस के चारों ओर रांची पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। सत्र के दौरान तीन लेयर की सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। विधानसभा की ओर आने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गयी है। बिना अधिकृत पास के कोई भी विधानसभा परिसर के अंदर नहीं जा सकता है।

न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं स्पीकर : प्रतुल शाहदेव

प्रमुख संवाददाता। रांची

भाजपा ने स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को उनके डेमोग्राफी में बदलाव से इनकार करने वाले बयान पर घेरा. प्रदेश प्रवक्ता प्रताप शाह देव ने कहा कि डेमोग्राफी बदलाव का मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचारार्थ है। उच्च न्यायालय ने सीमावर्ती 6 जिलों के उपायुक्तों को इस मुद्दे पर शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि उनके जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं और उनको कैसे निकाला जाए। उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय सुनाने के पहले ही स्पीकर का इस मामले में हस्तक्षेप करना सीधे तौर पर उच्च न्यायालय की अवमानना है। घुसपैठियों को संताल के मदरसों में ठहराया जाता है : प्रतुल ने कहा एक तरफ स्पीकर डेमोग्राफी में बदलाव से इनकार कर रहे हैं जबकि देश की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों में 1951 से 2011 के बीच संताल के इलाके में आदिवासियों की आबादी 16% घटी है और मुसलमान की आबादी 13% बढ़ी है। यह सीधे तौर पर घुसपैठ का मामला है। 1951 से 2011 के 60 वर्षों के कार्यकाल में 85% समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तो इस घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें जिम्मेदार हैं। प्रतुल ने कहा 2 जून, 2023 को सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र लिखकर स्पेशल ब्रांच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि घुसपैठियों को संताल के मदरसों में ठहराया जाता है और उनके सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। प्रतुल ने जानना चाहा कि क्या स्पीकर राज्य सरकार के स्पेशल ब्रांच से भी सहमत नहीं हैं? स्पीकर एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं और विचारार्थीन मामलों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। स्पीकर को अपने संवैधानिक कुर्सी की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।

बासी रोटी को नए प्लेवर में परोसने की कोशिश : कांग्रेस

झारखंड से क्या कमाया और क्या दिया, यब सब जनता देख रही है

विशेष संवाददाता। रांची

आनेवाला विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ही भाजपा ने हथियार डाल दिए हैं। यही कारण है कि भाजपा नेता अपनी शुभचिंतक केंद्रीय एजेंसियों के पास लगातार दौड़ लगा रही है। भाजपा ने एक झूठ का पिटाग अपने पास रखा है और इतना निराशा भाजपा नेता चुनावी धारा को मोड़ने के लिए रोज एक नया झूठ अपने पिटाग से निकाल रहे हैं। ये बातें प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कही। उन्होंने कहा कि झारखंडी जनता भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से हिसाब लेने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने झारखंड से क्या कमाया और झारखंडी जनता को क्या दिया. केंद्र को सबसे ज्यादा राजस्व देनेवाला झारखंड केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं के मामले में निचले पायदान पर है. वर्तमान केंद्रीय बजट

पेज एक का शेष

खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी... चौफ जॉस्टिस ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले दिये हैं और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो अहम सवाल थे. क्या 'रॉयल्टी' को टैक्स के समान माना जा सकता है? क्या राज्य विधानमंडल जमीन पर टैक्स लगाते समय जमीन की उपज के मूल्य के आधार पर टैक्स का उपाय अपना सकता है?

हाई बोल्ड का नंगा तार...

इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह पार्टी से बड़े हो गये हैं या अपरिहार्य हैं. उन्हे जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था. वे केवल इशारा कर दें तो वह अपने मठ में लौट जायेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इतना गरल पीया है कि वह नीलकंठ बन गये हैं. उनसे पूछे बगैर मुख्य सचिव बनाये, हटायें गये. केंद्र की इच्छा पर ऐसे अधिकारी को मंत्री बनाया गया जो चार चोट भी नहीं जुगाड़ सकता. ऐसे मुंहफट, बदमिजाज नेताओं को मंत्री बनाना पड़ा जो योगी जी को गालियाँ देते रहे हैं. इस बार टिकट बंटवारे में भी उनकी राय नहीं सुनी गयी. एक संगठन मंत्री तो छाया मुख्यमंत्री बने बैठे थे. योगी के भ्रुकुटि तानने पर वे हटे तो बाद में भेजे गये संगठन मंत्री पैतरेबाजी में मशगूल हो गये. प्रदेश अध्यक्ष ऐसे महानुभाव को बनाया गया जो न कोई चुनाव जीत सकते हैं, न किसी को जिता सकते हैं. जो उप मुख्यमंत्री कथित रूप से बगावत का झंडा उठाये हुए हैं और जिनके बयानों को आधार बनाकर योगी विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, वे अपनी विधानसभा सीट तक हार चुके हैं. एक उप मुख्यमंत्री बसपा से आये हैं और सिर्फ बोलकूड़ हैं. यानी यदि योगी को बलि का बकरा बनाया गया और उन्होंने मुंह खोल दिया तो नीचे से ऊपर तक समूची भाजपा हिल जायेगी. वह एक हाई बोल्ड का नंगा तार है. यदि फ्रिड से बिना लाइन कटो किसी ने छू लिया तो वह खाक हो जायेगा. वह कल्याण सिंह वाली गलती भी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुछ नहीं बोला है. वह मोदी जी से तादत्यम बैठायें हुए हैं. वह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की है. वह वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं हैं. वह शिवराज सिंह चौहान सरीखे हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश से हटाने के बाद केंद्र में समायोजित करना पड़ा है.

2017 में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार थे. तब वह प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की थी. तब योगी जी मुख्यमंत्री पद की रेस में भी नहीं थे. वह तो गोरखपुर में अपनी दिनचर्या में मस्त, व्यस्त थे. रेस में थे मनोज सिन्हा, वह भी केंद्र की कृपा से. लेकिन योगी जी को ल्याया गया तो कोई बड़ा कागज तो रहा ही होगा. वैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कोई नयी बात तो कही नहीं थी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है. यह तो जनसंघ के जमाने से भाजपा का ध्येय वाक्य है. इसे योगी के विरुद्ध क्यों देखा चाहिए? उसी बैठक में योगी ने कहा था कि हमें अति आत्मविश्वास ले डूबा. इसका क्या अर्थ लगाया जाये? यह किसके विरुद्ध है? इसी बीच अखिलेश यादव ने मौर्य साहब को मानसून और दे दिया- 100 विधायक लोओ, मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाओ. लेकिन उन्होंने डिक्टाउंट की घोषणा नहीं की. यानी उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी या मौर्य की सरकार को बाहर से समर्थन देगी.

दरअसल सभी विपक्षी पार्टियाँ चाहती हैं कि योगी जायें तो उनकी राजनीति फले-फूले, क्योंकि योगी ने जो लकरी खींची है उससे बड़ी लकरी खींचने की कुव्वत उन नेताओं में नहीं है. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि योगी राज में सब कुछ ठीक है. कार्यकर्ता मायूस हैं, अप्सरत उनकी नहीं सुनते हैं. लेकिन संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कर क्या रहे हैं? क्या उन्होंने सरकार से इस बाबत कभी बात की? सम्बन्ध का काम देकर रहे सहायक/बहा क्य कर रहे हैं? पेपर लीक एक बड़ी समस्या है. यह योगी पर एक धब्बा है. इसका इलाज उन्हें करना ही होगा. लेकिन यदि पार्टी के कुछ नेता और सहयोगी दलों के महारथी योगी पर प्रत्यक्ष-परोक्ष आरोप लगाते रहे, तब कसते रहे तो हालात और बिगड़ेंगे. वह भी हाड़-मांस, शिराओं-धमनियों से बने व्यक्ति हैं. कितना सहेंगे, कब तक सहेंगे. तुलसी ने लिखा ही है-अतिशय राग करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई. यह अनल प्रकट न हो, पार्टी धक्कने-जतने से बच जाये, इस बाबत तुरंत उपाय जरूरी है. योगी को हटाने से बात बनती है तो उन्हें कहीं सम्मान सहित रिश्क किया जा सकता है. लेकिन बिना सावधानी, सतकता के कोई इन्हे छुएगा तो जल जायेगा.

**कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं**

**जितेंद्र कुमार सिंह थाना प्रभारी**

बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह

**कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं**

**सदीक अंसारी मुखिया**

पंचायत-भधवाडीह, प्रखंड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह

**कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं**

**इंकज कुमार**

बाल अधिकार कार्यकर्ता, प्रखंड-तिसरी, जिला-गिरिडीह

**कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं**

**राजू कुमार मंडल उर्फ राजू भारती**

मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे, भाजपा, अहिल्याएर मंडल, प्रखंड-गाडेय, जिला-गिरिडीह

**कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं**

**ती आदर्श, चंदवा**



# भारी बारिश के बीच कई राज्यों में बने बाढ़ के हालात



पुणे

## पुणे में 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

एजेंसी। पुणे/मुंबई

मॉनसून की बरसात के कारण महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पुणे शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सिंहाड रोड और नदी तट से सटे अन्य इलाकों में बाढ़ आने के बाद बृहस्पतिवार को सेना की दो टुकड़ियों को बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित सिंहाड रोड पर तैनात किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दमकल के दलों के साथ-साथ जिला और नगर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कर्मियों को भी राहत अभियान में लगाया गया है। सिंहाड रोड के निचले इलाकों में स्थित कई हाउसिंग सोसाइटी और घरों में पानी घुस गया। जिला कलेक्टर सुहास दिवसे ने कहा, 'सिंहाड रोड से अबतक 400 लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।' पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि सेना के कर्मी सिंहाड रोड में एकता नगर में राहत अभियान में मदद कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पुणे जिले के वास्ते अगले 48 घंटे के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है और खडकवासला और अन्य बांधों के



### भारी बारिश के बीच तीन की करंट लगने से मौत

पुणे में बृहस्पतिवार तड़के भारी बारिश के कारण पानी में डूबे ठेके को बाहर निकालने की कोशिश करते समय करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना डेवकन जिमखाना इलाके में हुई। डेवकन जिमखाना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों बाबा भिडे पुल के पास सड़क किनारे ठेका पानी में डूब गया, तो वे मौके पर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे, इस दौरान तीनों को करंट लग गया।

जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अंदेश है तथा खडकवासला जलाशय से अधिक पानी छोड़े जाने के आसार हैं। पुणे जिले में झरने और झील जैसे पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के अलावा निजी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों से कहा गया है कि वे कर्मियों को एक दिन की छुट्टी दें। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्रियों अजित

पवार और देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई, ठाणे और पुणे शहरों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पुणे में बारिश से प्रभावित लोगों को हवाई मार्ग से निकाला जाएगा। उन्होंने पुणे के जिलाधिकारी और शहर तथा पड़ोसी औद्योगिक नगर पिंपरी चिंचवड के नगर निकाय प्रमुखों से बात की है।

मॉनसून की बारिश के बीच देश देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई। इसके कारण कई नदियों के उफान पर आने के साथ ही कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पुणे में बारिश के बीच करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि ठेका हटाने की कोशिश कर रहे तीन लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं मुंबई में सड़कों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हुआ। साथ ही ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई। 'रेड अलर्ट' को देखते हुए मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया। इस बीच, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी वर्षा के चलते सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ का खतरा टालने के लिए राज्य सरकार ने कर्नाटक से अलमाटी बांध से अधिक पानी छोड़ने का आग्रह किया है। मंगलुरु में घर की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एकिशोर की मौत हो गई।



सूरत

## मुंबई में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, ट्रेन सेवा हुई प्रभावित

मुंबई। मुंबई और उसके उपनगरों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई जिससे कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। इसके चलते यातायात बाधित हुआ और लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण विहार और मोदक सागर झीलें उफान पर हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ ही महानगर को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाले सात जलाशयों में से चार अब उफान पर हैं, जिससे कुल जल भंडार में सुधार हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटों में सुबह आठ बजे से शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी वर्षा व कुछ स्थानों पर अत्याधिक बारिश होने की संभावना जताई है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई और इसके पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में सुबह से ही भारी बारिश होने के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे द्वारा संचालित उपनगरीय सेवाएं 10-15 मिनट देरी से चल रही हैं। वहीं भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी करने के बाद, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया।

### देश के मौसम का हाल

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान, गुजरात, कोंकण और गोवा और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो बार भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मराठवाड़ा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

## गुजरात में उफान पर नदियां, सूरत व भरुच में आई बाढ़

सूरत। गुजरात में इन दिनों भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां उफान पर हैं। पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दक्षिण और मध्य गुजरात के सूरत और भरुच समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क मार्ग कट जाने से कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। इसके अलावा कई सड़कों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रेक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जबकि कुछ ट्रेनों को रेलुलेट किया

### मंगलुरु में भारी वर्षा से दीवार गिरी, युवक की मौत

मंगलुरु (कर्नाटक)। मंगलुरु में बुधवार रात भारी वर्षा के बीच कोलनाड गांव के लिंगप्पय्या कडु में एक घर की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मृतक की पहचान मुल्की के कोलनाड गांव के लिंगप्पय्या कडु निवासी शैलेश

(17) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार भारी बारिश के कारण देर रात्रि मकान की दीवार ढह गई जिसके नीचे दबने से शैलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

### हिय में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद एनएच-3 का एक हिस्सा किया गया बंद

शिमला/मनाली। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-तीन के एक हिस्से को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार देर रात हुई इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार मनाली क्षेत्र में अंजनी महादेव नाले में बादल फटने के कारण एनएच-3 पर धुंधी और पलवना के बीच का हिस्सा प्रभावित हुआ है। लाहौल और स्पीति पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक परामर्श जारी कर कहा कि अटल टनल के उत्तरी द्वार से लाहौल और स्पीति से मनाली जाने वाले वाहनों को रोहतांग की ओर मोड़ दिया गया है। यात्रियों से यह भी कहा कि वे



केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, सावधानी से वाहन चलाएं तथा मार्ग में संभावित खतरे के प्रति सचेत रहें। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि बुधवार रात में राज्य में कुल 15 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं।

### त्रीफ खबरें

#### चीन हिंद महासागर में कर रहा है घुसपैठ

वाशिंगटन। अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि चीन हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रहा है, जिससे अमेरिका और दक्षिण एशिया में उसके मित्र देशों और सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी सांसद में यंग किम ने कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

#### छग में पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पांच नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि नक्सलियों पर कुल 19 लाख रुपये का इनाम घोषित है। एसपी ने बताया कि नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। वे अपने वरिष्ठ माओवादीयों द्वारा किए गए अन्यायों और 'अमानवीय' और 'खोखली' विचारधारा से निराश हैं।

#### श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख लड़ेंगे चुनाव

कोलंबो। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख और लिट्टे के सफाए के लिए सैन्य अभियान के सूत्रधार फील्ड मार्शल सरथ फोसेका ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की बृहस्पतिवार घोषणा की और भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प जताया। देश में राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। वह वर्ष 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे।

## मॉरिटैनिया में जहाज दुर्घटना में 25 प्रवासियों की मौत, 190 लापता

शुभम संदेश न्यूज नेटवर्क। नयी दिल्ली

मॉरिटैनिया की समाचार एजेंसी के अनुसार, देश के समुद्र तट पर एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें अभी तक 25 प्रवासियों के मौत की खबर है और कई लापता भी हैं। यह घटना राजधानी नौआकचोट के पास हुई है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने कहा कि 190 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मॉरिटैनियाई तटरक्षक ने 103 प्रवासियों को बचाया है और 25 शव बरामद किए हैं। आईओएम ने कहा कि गार्बिया से लगभग 300 लोग एक लकड़ी की नाव पर सवार होकर निकले थे और 22 जुलाई को नाव के पलटने से पहले वे समुद्र में सात दिन का सफर कर चुके थे। कोस्टगार्ड के पहुंचने से पहले 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 10



### डूबा जहाज, नौ लोग थे सवार

ताइवान के दक्षिणी तट पर मालवाहक जहाज के डूबने के बाद राहतकर्मियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जहाज में चालक दल के नौ सदस्य सवार थे, ताइवान के तटी से गेमी तूफान के टकराने के वक्त यह जहाज दक्षिणी शहर काओशुंग के बंदरगाह के पास था। तूफान के कारण फिलीपींस में लगातार बारिश हो रही है, जहां ईंधन ले जा रहा एक टैंकर डूब गया था।

लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसे ही एक घटना 5 जुलाई को हुई थी जिसमें मॉरिटैनियाई तट रक्षकों ने 89 प्रवासियों के शव बरामद किये थे।

## मानहानि मामले में कल सुलतानपुर की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी

सुलतानपुर (उप्र)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में 26 जुलाई को सुलतानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में हाजिर होंगे। कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बृहस्पतिवार को बताया कि राहुल गांधी 26 जुलाई को पूर्वांचल नौ बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह कार से सुलतानपुर के लिये रवाना होंगे और अदालत में पेश होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बैंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी।

## कर्नाटक: भाजपा विधायक व एमएलसी ने विस के अंदर रातभर अनोखे तरीके से दिया धरना

एजेंसी। बैंगलुरु

कर्नाटक में मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग तेज हो गई है। विपक्षी विधायकों, एमएलसी ने विधानसभा में अनूठे अंदाज में रात बिताई। सोशल मीडिया पर विपक्षी विधायकों और एमएलसी के वही कुछ विधायक विधानसभा के अंदर तकिए और कंबल लेकर पहुंचे और पूरी रात धरना दिया।

भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को मुडा घोटाले के विरोध में सदन के अंदर दिन-रात धरना देने का ऐलान किया था। भाजपा विधायक और एमएलसी पूरा रात विधानसभा में जमीन पर चादर बिछाकर सोए। सुबह उठे तो चाय की चुस्कियां लेते और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करते दिखे। बता दें कि विपक्ष को बुधवार को दोनों सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई थी।



### खास बातें

- कुछ विधायक घर से कंबल और बिस्तर लेकर पहुंचे थे
- मुडा घोटाले के विरोध में किया था धरना देने का ऐलान

विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज (शुक्रवार) भी पूरे दिन विधानसभा में भारी हंगामे के आसार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भूखंड हासिल करने वालों में कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया की

## राजस्थान में गोवंश के लिए अब 'आवारा' शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा

जयपुर। राजस्थान में गोवंश के लिए अब 'आवारा' शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में यह घोषणा की। कुमावत बुधवार रात विधानसभा में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मांग संख्या-47) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की 15.58 अरब रुपये से अधिक की अनुदान मांगों ध्वनित से पारित कर दी। मंत्री ने कहा, 'राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशु सम्पदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, गायाँ और बैलों के संरक्षण-संवर्धन के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आवारा गोवंश के लिए अब से 'निराश्रित' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।'

## नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का 'ब्लैक बॉक्स' हुआ बरामद

एजेंसी। काठमांडू

नेपाल में एक दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का 'ब्लैक बॉक्स' बरामद कर लिया गया है और यह जांच टीम को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दुर्घटना में एक बच्चे सहित 18 लोग मारे गए थे। सौंपे गए एयरलाइंस का पोखरा जा रहा 'बॉम्बार्डियर सीआरजे-200' विमान बुधवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। घटना में विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो गई और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में चालक दल के दो सदस्य, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी और चार वर्षीय एक लड़के सहित तीन लोगों का परिवार शामिल है।



नागर विमानन प्राधिकरण के उपमहानिदेशक हंस राज पांडे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का 'ब्लैक बॉक्स' बरामद कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच टीम को सौंप दिया गया है। जांच टीम का नेतृत्व नागर विमानन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रतीश चंद्र लाल कर रहे हैं और इसमें चार अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम को 45 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट और सिफारिश सौंपनी है।